वर्ष - 01, अंक - 02, जनवरी, 2023

# द डाटा स्ट्रीट

THE DATA STREET

मूल्य 30 रुपये

हिन्दी मासिक पत्रिका

## समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए आर्थिक-जातिय गणना जरूरी

संपादकीय

# संपादकीय,

देश और दुनिया में बढ़ते तकनीकी युग ने प्रिंट मीडिया को काफी पीछे छोड़ दिया है। आज इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया छोटी लग रही है। किसी विषय में जानकारी करने के लिए इंटरनेट से एक क्लिक पर मिल जा रही है। मोबाइल से लेकर कम्प्यूटर तक के उपयोग में क्रांति आ गई है। मजदूर से लेकर देश के प्रथम नागरिक के हाथों में मोबाइल आज आवश्यकता बन गई है।

यह सब सकारात्मक पहलू सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल और सोशल मीडिया एक ही विषय पर अपने.अपने तरीके से आकड़ों का विश्लेषण करते हैं। परिवार में बैठे बैठ अलग-अलग सदस्य बातचीत से ज्यादा मोबाइल का उपयोग करते दिखते हैं। इन सब सकारात्मकता के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नकारात्मक गंभीर पहलू है। आकड़ों को लेकर तथ्यात्मक जानकारी न होने के कारण काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। इन तमाम विसंगतियों को देखते हुये यूरीड मीडिया ग्रूप **'द डाटा स्ट्रीट'** नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की है जिसका दूसरा अंक प्रकाशित हो रहा है। प्रयास यह है कि आकड़ों की तथ्यात्मक जानकारी आप सभी तक पहुंचे और जैसे पूर्व में सहयोग मिलता रहा है, वैसे आगे भी मिलता रहे।

संपादक
**राजेन्द्र द्विवेदी**

# द डाटा स्ट्रीट

हिन्दी मासिक पत्रिका

**वर्ष - 01, अंक - 02, जनवरी, 2023**



संरक्षक –

जस्टिस आर एन पाण्डेय

(पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद)

**सम्पादक -** राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी

**स्थानीय संपादक -** विजय शंकर पंकज

**समाचार संपादक -** सुजीत श्रीवास्तव

**स्टेट ब्यूरो यू पी -** अमन सिन्हा

**ब्यूरो चीफ -** रोहित सिंह

**यूपी-उत्तराखण्ड प्रभारी -** जीतेन्द्र सिंह चौहान

**दिल्ली ब्यूरो -** अतुल कुमार

**कोलकाता ब्यूरो -** सुशांतो बनर्जी

**चेन्नई ब्यूरो -** कुमार देवेश

**देहरादून ब्यूरो -** पूजा बिष्ट

**हैदराबाद ब्यूरो -** इरफान

**अहमदाबाद ब्यूरो -** मोहित जडेजा

**गुवाहाटी ब्यूरो -** देवास्वरूप बरूआ

**विधि सलाहकार -** संतोष शुक्ल (अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ बेच)

**ग्राफिक्स एवं डिजाइन -** बसंत चौहान



कार्यालय: डी– 1/132, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010 मोबाइल: 9415020028

ईमेल – uridmedia24@gmail.com



स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्वास्तिक प्रिन्टिंग प्रेस 27 माई की बगिया बड़ा चांदगंज लखनऊ उ0 प्र0– 24 से मुद्रित डी–1/132, विराज खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, यू0पी0–226010 से प्रकाशित



उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पी0 आर0 बी0 अधिनियम 1867 की धारा 7 के अन्तर्गत पत्रिका में प्रकाशित समस्त लेखों की जिम्मेदारी सम्पादक की होगी।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।


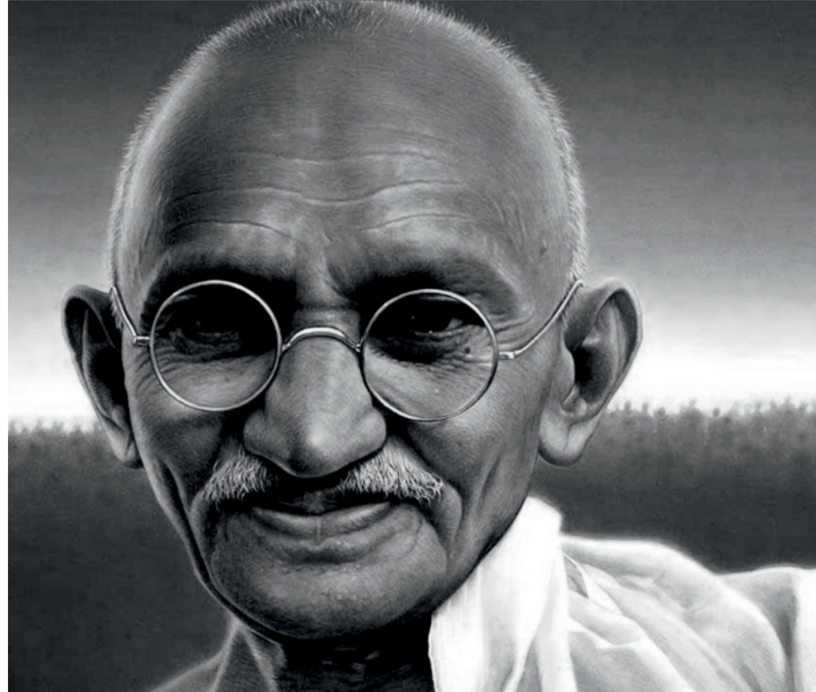

## विषय सूची


समाज के अंतिम व्यक्ति के न्याय के लिए जातिगत/आर्थिक जनगणना जरूरी........................ 05

गाँधी, अम्बेडकर, लोहिया और दीन दयाल की सोच समाज के अन्तिम व्यक्ति को लाभ देने के ................ 10

रेवड़ी कल्चर.................................................................. 18

राजनीतिक गलियारा ...................................................... 31

अन्तिम दौर में पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा..... 35

जोशीमठ का दर्द ................................................... 41

नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2014 से 1.7 गुना बढ़ी ........................................ 45

पिछले ढाई दशक से हम डाटा से जुड़े कार्य कर रहे हैं। पोर्टल के माध्यम से निरंतर डाटा से जुड़ी खबरें एवं जानकारी दी जाती रही हैं। विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव परिणाम की विश्लेषणात्मक पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। 'द डाटा स्ट्रीट' पत्रिका में समाज से जुड़ी विभिन्न खबरें, चुनाव विश्लेषण व केंद्र एवं प्रदेश सरकार के योजनाओं की जमीनी हकीकत, डाटा आधारित जानकारी दी जाएगी। पत्रिका एवं पोर्टल दोनों डाटा आधारित होंगे।

# समाज के अंतिम व्यक्ति के न्याय के लिए जातिगत/आर्थिक जनगणना जरूरी

☐ राजेन्द्र द्विवेदी

देश में 75 वर्षों बाद भी केंद्र सरकार एवं राज्यों के पास सामाजिक आर्थिक व जातियों के अनुसार सही आकड़ें नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा देश भर में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं सामान्य वर्गों सहित समाज के सभी तबकों के लिए 1000 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 से 2022केबीच 300 से अधिक नई योजनाएं शामिल है। राज्यों ने भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लिए योजनाएं चलाई हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या में भी काफी विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जातिगत और आर्थिक गणना बहुत जरूरी है। जिस दिन आर्थिक और जातिगत गणना की वास्तविक तस्वीर आ जाएगी। देश के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार एवं सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाने में काफी पारदर्शिता और सहायक होगी। यह अलग बात है कि जाति के नाम पर राजनीतिक दलों की दुकानें लगभग बंद हो जाएंगी। बिहार जोकि देश के अति पिछड़ें राज्यों में शामिल है वहां पर जातीय और आर्थिक गणना की शुरूआत 7 जनवरी 2023 से करके नितीश कुमार की

सरकार ने अनुकरणीय फैसला किया है। निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ बिहार सरकार ने जाति और आर्थिक गणना करके योजनाएं बनायी तो निश्चित रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा और बिहार की तस्वीर अन्य पिछड़े राज्यों से अलग हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 से लेकर 2022 तक 300 से अधिक शुरू की गयी गरीबों, पिछड़ों एवं समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ देने की योजनाएं आकड़ों की विसंगतियों के कारण समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में योजनाओं के लाभान्वित परिवार और सरकारी आकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो काफी विसंगतियां मिलेगी और इन्हीं विसंगतियों के कारण निचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गयी है कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जैसे ईमादार और डबल इंजन सरकार दूर नहीं कर पायी है। कई योजनाओं को लेकर अलग.अलग जनपदों में सरकारी आकड़े और लाभार्थी का विश्लेषण करने पर विसंगतियां मिल रही हैं। हर योजना के विसंगतियों पर एक पुस्तक तैयार हो सकती है।

संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आबादी के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो आज भी लागू है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की दूर दृष्टि समाज के गरीब पिछड़ें वर्गों के उत्थान, दलितों के साथ-साथ समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ें वर्गों तथा समाज के अंतिम व्यक्ति को हिस्सेदारी मिले इसके लिए 29 जनवरी 1953 में काका कालेकर आयोग का गठन किया था। आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें पहली संस्तुति ही 1961 में होने वाली जनगणना को जातिवार जनगणना कराने की थी। दूसरा देश में 2999 पिछड़ी जातियों में 837 अति पिछड़ी जातियां चिन्हित की। आर्थिक स्थिति दलितों जैसी थी। तीसरी संस्तुति महिलाओं को लेकर थी। जिसमें उन्होंने सभी वर्ग की महिलाओं को पिछड़ा माना था। संस्तुति थी कि महिलाओं के उत्थान के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। काका कालेकर की रिपोर्ट पर राज्यों में आम सहमति न होने के कारण 1961 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्यों को पिछड़ें.पन की परिभाषा तय करने के लिए अधिकार दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में अप्रैल 1968 में मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, कर्नाटक सरकार ने अगस्त 1972 में एस के हवाना की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, बिहार सरकार ने जून 1971 में मुंगेरी लाल की अध्यक्षता

**देश की सियासत की धुरी राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी, भीम राव आम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और दीन दयाल के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के सोच पर ही की जा रही है। केंद्र हो या राज्य सभी दल इन्हीं महापुरुषों का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं।**

में पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश में 1975 में छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, पंजाब में 1965 में वृषभानु की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, केरल में वी के शिवनाथन की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग, तमिलनाडू में ए बीसत्यानाथन आयोग का गठन किया। राज्यों ने इन रिपोर्टों के आधार पर राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण की व्यवस्था में फेरबदल किया। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह अधूरा रहा। 1977 में गैर.कोंग्रेसी सरकार बनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 20 दिसम्बर 1978 को भूतपूर्व सांसद बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जिसमें आर आर भोले, पूर्व सांसद, आर एल नायर, भूत पूर्व सांसद, दीवान मोहन, एस एस गिल शामिल थे। जिसने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 21 दिसम्बर 1980 सौंप दी। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार के पतन और केंद्र में इन्दिरा गांधी की सरकार बनने के बाद यह रिपोर्ट

ठंडे बस्ते में डाल दी गई।

1989 में दूसरी बार गैर काँग्रेस सरकार वी0 पी0 सिंह के नेतृत्व में बनी। इस सरकार के आपसी द्वंद के कारण वी0 पी0 सिंह और देवी लाल में पिछड़ें वर्ग की राजनीति को लेकर तना-तनी हो गई। देवीलाल ने **13 अगस्त 1990** को पिछड़ों की रैली आहूत करने की घोषणा की थी। इससे घबराय वी0 पी0 सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा में भी मण्डल कमीशन की आधी-अधूरी रिपोर्ट को ही लागू किया और तमाम चीजों को भ्रम जाल में उलझा दिया।

मण्डल कमीशन ने पिछड़ें वर्ग के उस आबादी को सरकारी नौकरियों, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 27% आरक्षण देने की मांग की थी जो समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट गये थे। मण्डल आयोग ने पिछड़ी जाति की बात न करके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ो की पहचान करने की मांग की थी। मण्डल ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि **"जाति के आधार पर कोटा आवंटन नस्लीय भेदभाव का एक रूप है और समानता के अधिकार के विपरीत है।"** मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों जिसमें मुसलमान भी शामिल है, आयोग ने पिछड़ों के 27% आरक्षण की संस्तुति की थी। वी पी सिंह ने राजनीतिक कारणों से पिछड़ें को जोड़ने और देवीलाल की रैली कमजोर करने के लिए लागू की गयी रिपोर्ट में समाज के अति पिछड़ों को शामिल नहीं किया गया। जिसका लाभ कुछ जातियां उठाती रही। मंडल कमीशन के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद रहे एलआर नायक ने अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की संस्तुति की थी।

## नौकरियों में आरक्षण

यह पहल एक दल या एक सरकार नहीं कर सकते इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ जुटकर आना होगा या आम सहमति न बनने पर प्रधानमंत्री जैसे साहसिक नेता कदम उठाकर संवैधानिक दायरे में एक परिवार को एक बार आरक्षण जैसे नौकरियों या फिर जनप्रतिनिधि सांसद, विधायक के लिए क्यों न हो सभी पर सामान रूप से लागू होना चाहिए। इसका सीधा फार्मूला ग्राम पंचायत सदस्य के बाद प्रधान, क्षेत्र पंचायत

सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, विधायक, सांसद एवं नौकरियों में चपरासी से लेकर आईएएस तक लागू होना चाहिए।

- समाज के कई क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न संगठनों एवं बुद्धिजीवियों से चर्चा के बाद आर्थिक रूप से पिछड़ी विभिन्न जातियों के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए लागू किया जाना चाहिए।
- यह बहुत सीधा और सरल है। प्रथम, जातीय आधार पर गणना की जानी चाहिए।
- जातियों में आर्थिक आधार पर गणना होनी चाहिए।
- आर्थिक एवं जातिगत गणना के सही आकड़े को पारदर्शी तरीके से व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। उसी आधार पर योजनाओं के लाभ देने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

नौकरियों में एक परिवार को एक बार आरक्षण का फार्मूला लागू होने के लिए आरक्षित वर्ग के जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल चूका हो उसे दूसरी बार नहीं मिलना चाहिए। इसका भी एक फार्मूला हो जिसमें चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण मिलने के बाद लाभान्वित परिवार को चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण नहीं देना चाहिए लेकिन उसे आरक्षण का लाभ तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए। यही स्थिति तृतीय श्रेणी के नौकरी में आरक्षण पाने वाले को तृतीय श्रेणी में नहीं मिलाना चाहिए जबकि द्वितीय और प्रथम श्रेणी में मिलाना चाहिए। द्वितीय श्रेणी में लाभान्वित परिवार को दूसरे श्रेणी में नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी में अवसर दिया जाना चाहिए। प्रथम श्रेणी में आरक्षण पाने वाले परिवार को आरक्षण श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए ताकि दूसरे परिवार को भी मौका मिले क्योंकि नौकरियों की संख्या सीमित है। नौकरियों में आरक्षण पाने वाले परिवारों की संख्या बहुत अधिक है। सरकारी सर्वे में आरक्षण के जो आकड़ें आये है उसके अनुसार आरक्षण का लाभ कुछ ही जाति एवं परिवारों तक सीमित हो कर रह गया है।

व्यावहारिक रूप से यह देखा भी जा रहा है कि जो आरक्षित वर्ग का अधिकारी बन गया वह आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संपन्न है उनके बच्चे देश एवं प्रदेश के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए इन बच्चों से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार जिनकी पढाई सरकारी स्कूलों में होती है आर्थिक रूप से कमजोर है उनसे नहीं की जा सकती है और वह आरक्षित वर्ग की नौकरियों में अवसर पाने से वंचित रह जाते है।

## जनप्रतिनिधियों में आरक्षण

जातीय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े की गणना आने के बाद ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर सांसद तक आरक्षित सीटों में भी नौकरियों का फार्मूला लागू किया जाना चाहिए। जिस पद पर आरक्षण का लाभ मिल चुका हो उस जनप्रतिनिधि के पद पर लाभान्वित परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आरक्षित वर्ग पर लाभान्वित परिवार को उस पद पर लाभ नहीं मिलना चाहिए लेकिन उसके लिए अन्य प्रधान, विधायक सांसद का अवसर मिलना चाहिए यही स्थिति शहरी निकायों में सदस्य व पार्षद का लाभ लेने वाले को इस पद पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए लेकिन उसके लिए अध्यक्ष, मेयर विधायक सांसद के पद पर आरक्षण का अवसर मिलाना चाहिए।

- पिछड़ों के आरक्षित श्रेणी में एल आर नायक की संस्तुति को भी शामिल किया जाना चाहिए।

## मण्डल कमीशन

मण्डल कमीशन के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद रहे एल आर नायक ने बी0 पी0 मंडल के पिछड़ों को 27% आरक्षण देने पर सहमति व्यक्त की थी लेकिन

एल आर नायक
राज्य सभा, मण्डल कमीशन के सदस्य

उन्होंने अपनी अलग से संस्तुति दी थी और कहा था कि पिछड़ों में अति पिछड़ी जातियां हैं जिनकी स्थिति अनुसूचित जाति एवं अनु सूचित जनजातियों जैसी है। इसलिए उन्हें 27 में से 15 प्रतिशत अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनका मत था कि पिछड़ों को मंडल कमीशन में 27 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गयी है उसे दो वर्गों में विभाजित किया जाये। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग।

**नौकरियों में आरक्षण पाने वाले परिवारों की संख्या बहुत अधिक है। सरकारी सर्वे में आरक्षण के जो आकड़ें आये है उसके अनुसार आरक्षण का लाभ कुछ ही जाति एवं परिवारों तक सीमित हो कर रह गया है।**

पिछड़े वर्ग को 12% तथा अति पिछड़ें वर्ग को 15% आरक्षण की व्यवस्था की जाये जिससे कि अतिपिछड़ों एवं कमजोर पिछड़ों का हक़ प्रभावशाली पिछड़े न खाने पाए। जैसे कि एक तालाब में छोटी और बड़ी मछली को एक साथ रखने पर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वी पी मंडल में एलआर नायक की संस्तुति आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अतिपिछड़ों के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गयी। जिसके कारण पिछड़े वर्ग की प्रभावशाली जातियां ही अतिपिछड़ी जातियों का हिस्सा खा गयी।

प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण उत्थान के लिए आर्थिक व जातिगत आकड़ों के लिए प्रभावी पहल नहीं हुई। काका कालेकर और बी पी मण्डल दो राष्ट्रीय आयोग एवं प्रत्येक राज्य स्तर पर आयोगों का गठन होता रहा। लेकिन आर्थिक एवं जातिगत आधार पर आजादी के 75 वर्ष बाद भी अतिपिछड़ों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

देश की सियासत की धुरी राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी, भीम राव आम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और दीन दयाल के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के सोच पर ही की जा रही है। केंद्र हो या राज्य सभी दल इन्हीं महापुरुषों का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर उभरे जातीय नेता अपनी-अपनी जाति के नाम पर पार्टी बनाकर सियासत कर रहे हैं। जातीय आधार पर बनी पार्टी परिवार के उत्थान तक सीमित हो कर रह गयी हैं।

"The ancient adage that 'if a big fish and a small fish are put together, the former will swallow the later', is still very apt in the context of the caste hierarchical society of India. Care should, therefore be taken with all emphasis at our command that the benefits of safeguards are dispersed equitably and rationally, as far as possible among all sections of the backward classes. This, I consider, can happen by avoiding competition for benefits among unequals or by bringing about competition among equals. I, therefore, propose that the common list should be categorised into two parts, 'A' and 'B'; 'A' consisting of those classes whom I have described as 'Depressed Backward Classes' and 'B' the rest of the communities in the list to be described as 'Intermediate Backward Classes'.

In all fairness and in view of the fact that the 'Depresses Backward Classes' are comparable in matters of backwardness to those of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I recommend 15 percent reservation for them out of 27 percent both in public services and educational institutions as mentioned above. For all other concessions they should be treated on par with SC/ST............"

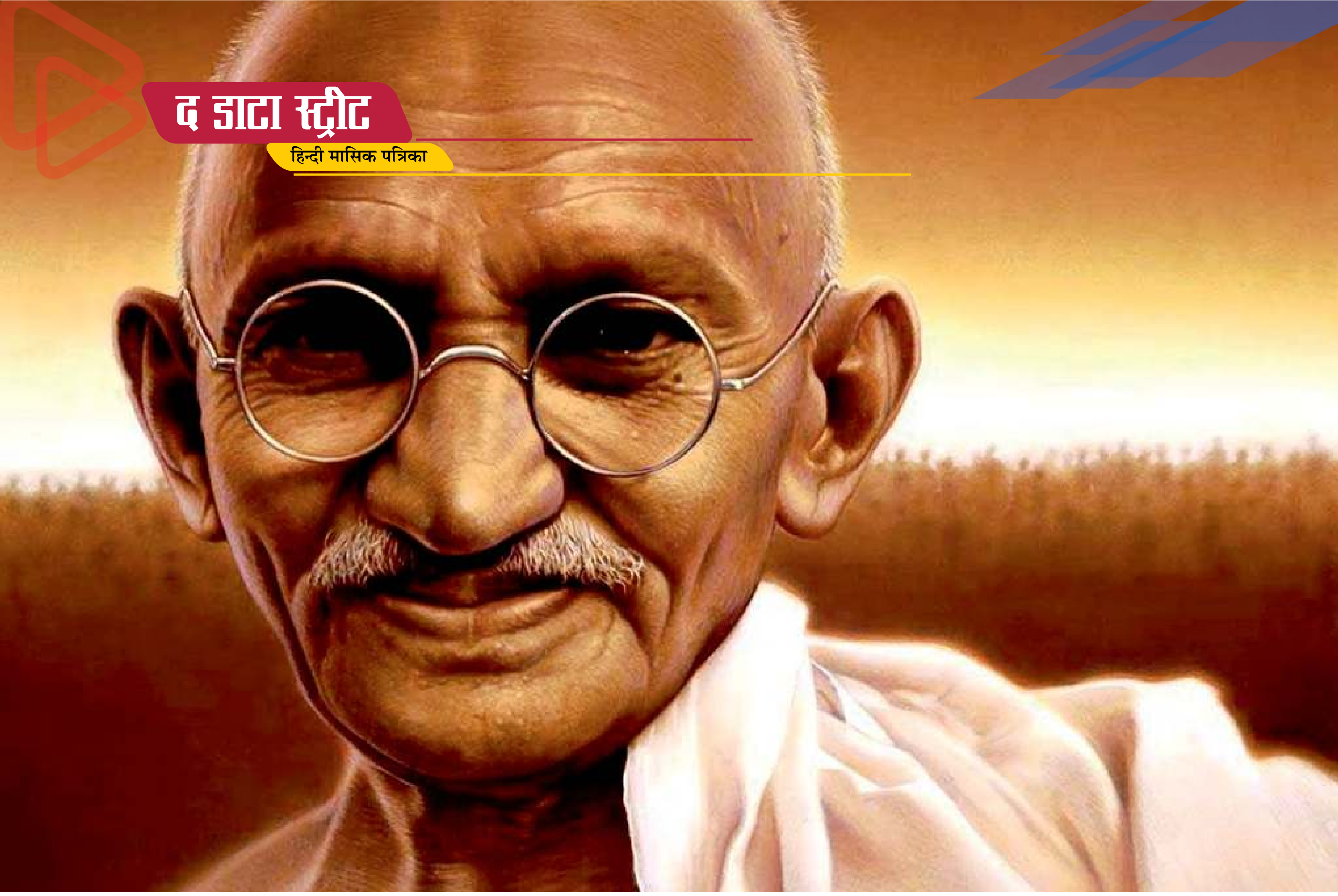

# गाँधी, अम्बेडकर, लोहिया और दीन दयाल की सोच समाज के अन्तिम व्यक्ति को लाभ देने के लिए एक जैसी

**◻ राजेन्द्र द्विवेदी**

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉ भीम राव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चारों की सोच समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए एक ही रही है। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 75 वर्षों में अम्बेडकर, दीन दयाल और लोहिया के अनुयायी राजनीतिक दल समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए पारदर्शी और निष्पक्षता पूर्वक कदम नहीं उठाया। जिसका दुष्परिणाम यह है कि आज समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की संभावना जाति की सियासत करने वाले नेताओं ने और हाशिए पर पंहुचा दिया है।

**प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के पहल से अन्य गैर कोंग्रेसी और अन्य भाजपा सरकारें भी आर्थिक और जातिगत गणना कराने पर मजबूर हो जाएंगी। आजादी का 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।**

संविधान निर्माताओं ने समाज के सबसे गरीब तबके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की थी। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था केवल 10 वर्षों के लिए ही थी। बदलते राजनीतिक समीकरण में पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की मांग उठी। इसके लिए बीपी मण्डल के अध्यक्षता में मण्डल कमीशन का गठन किया गया। छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति गठित की गई। करपुरी ठाकुर आयोग गठन किया गया। काला कालेकर आयोग सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आरक्षण को लेकर कई आयोग एवं कमेटियाँ बनी। सबने अपनी.अपनी संस्तुति दी। इन सबकी संस्तुतियों में एक बात कामन है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण के लिए गठित कमेटियों के नाम पर आरक्षण देने के लिए देश भर में जातीय पार्टियां बनी। इन जातीय पार्टियों ने समाज के अंतिम व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में मदद करने के बजाय अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया। जाति के नाम पर बने दल, बात अपनी.अपनी जातियों की करते है लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात हो या सरकारी सेवाओं में अवसर पाना हो तो बढ़ावा परिवार और रिश्तेदार को ही दे रहे हैं। आरक्षण के नाम पर संविधान में कई बार संशोधन हो चुके हैं।

आजादी के 75वर्ष बाद देश एवं समाज में गरीब अमीर अगड़े-पिछड़े के बीच की खाई और गहरी हो गयी है। गरीब गरीब होता जा रहा है और आरक्षण का लाभ लेकर दलित और पिछड़ों में कुछ परिवार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो स्वयं को गरीब और पिछड़ा मानते है। गरीब की वेदना को व्यक्त करते समय उनके चेहरे पर वेदना भी दिखाई देती है। लोकप्रिय नेता है और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए मूल भूत आवश्यकताओं को लेकर शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी तमाम योजना भी चला रहे हैं। उन्हें आर्थिक एवं जातिगत गणना के लिए पहल करनी चाहिए जिससे सही आकड़े सामने आएं। समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले।

देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता राहुल गाँधी जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गरीब पिछड़ें दलितों किसानों की जमीनी हकीकत जानने के लिए 3700 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 109 दिनों में 3000 की यात्रा पूरी कर चुके हैं। राहुल गाँधी की नीति.नियत और मंशा को देखकर यह कहा जा सकता है

> **आजादी के 75वर्ष बाद देश एवं समाज में गरीब अमीर अगड़े-पिछड़े के बीच की खाई और गहरी हो गयी है। गरीब गरीब होता जा रहा है और आरक्षण का लाभ लेकर दलित और पिछड़ों में कुछ परिवार सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो गए हैं।**

कि उनकी पहल समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सार्थक हो सकती है।

दशकों तक केन्द्र में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने आर्थिक एवं जातिगत रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहल नहीं की उसे वर्तमान में बिहार सरकार की तरह कांग्रेस शासित राज्यों में आर्थिक एवं जातिगत डाटा एकत्र करके गाँधी और आम्बेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के सपने को साकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कांग्रेस के पहल से अन्य गैर कोंग्रेसी और अन्य भाजपा सरकारें भी आर्थिक और जातिगत गणना कराने पर मजबूर हो जाएंगी। आजादी का 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश में गांव गरीब किसान और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारे1000 से भी ज्यादा योजनाएं चला रही है लेकिन उसका आपेक्षित लाभ और तथ्यात्मक आकड़ों के आभाव में सही आर्थिक रूप से कमजोरों को लाभ नहीं मिल रहा है। स्थितियां बदली है। सरकारी

नौकरियां सीमित हो गयी हैं उनसे जातियों का भला नहीं हो सकता है। आर्थिक एवं जातिगत आकड़ें की गणना करके जनप्रतिनिधित्व का अधिकार देने की पहल होनी चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर पार्षद और सांसद तक आबादी और आर्थिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। पारदर्शी तरीके से पहल होनी चाहिए और ऐसी पहल बड़े बड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जब तक नौकरियों में आरक्षण और योजनाओं का लाभ आर्थिक व जातीय आधार पर पिछड़ें समाज के लोगों को ताकत नहीं मिल सकती तब तक उनकी भागीदारी जन प्रतिनिधित्व के रूप में ग्राम पंचायत सदस्य, पार्षद, सहकारी समितियों, विधायक एवं सांसद तक नहीं मिलेंगी। इसके लिए पारदर्शी फार्मूला ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। जन प्रतिनिधि एवं नौकरियों में एक ऐसा फार्मूला संवैधानिक दायरे में लेकर लागू करने की आवश्यकता है जिसमें एक बार आरक्षण का लाभ पाए परिवार को दूसरी बार आरक्षण तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक उस जाति के परिवार को लाभ नहीं मिल जाये। यह व्यवस्था दलित पिछड़े व सामान्य को दिए गए 10% आरक्षण सभी में लागू होनी चाहिए। यह पहल एक दल या एक सरकार नहीं कर सकते इनके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ जुटकर आना होगा या आम सहमति न बनने पर प्रधानमंत्री जैसे नेता साहसिक कदम उठकर संवैधानिक दायरे में एक परिवार को एक बार आरक्षण जैसे नौकरियों में या फिर जनप्रतिनिधि सांसद विधायक के लिए क्यों न हो सभी पर सामान रूप से लागू होना चाहिए इसका सीधा फार्मूला ग्राम पंचायत सदस्य के बाद प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यए ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, विधायक, सांसद एवं नौकरियों में चपरासी से लेकर आईएएस तक लागू होना चाहिए।

## राज्यों में आरक्षण

उत्तर प्रदेश में भी अति पिछड़ों को हक देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने 31 अक्टूबर 1975 को छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। जिसमे विधायक मलखान सिंह सैनी और विधायक सीताराम निषाद शामिल थे। साथी आयोग उत्तर प्रदेश का पहला आयोग था, जिसने पूरे प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों का अध्ययन करके 17 मई 1977 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने पिछड़े वर्गों की तीन श्रेणियाँ बनाकर 29.5 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। उन्होंने पहली श्रेणी में भूमिहीन और अकुशल मजदूरों को 17 प्रतिशतए दूसरी श्रेणी में दस्तकार और किसानों को 10 प्रतिशत और तीसरी श्रेणी में मुस्लिम पिछड़ी जातियों को 2.5 आरक्षण देने की संस्तुति की थी। किन्तु सरकार ने साथी आयोग की सिफारिशों को नहीं माना।

वी0 पी0 सिंह द्वारा मण्डल कमीशन लागू करने के बाद, आगड़ों-पिछड़ों के बीच संघर्ष हुआ और राज्यों से

लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जातीय ध्रुवीकरण हुआ। राज्यों में पिछड़ी जातियों के क्षत्रपों का वर्चस्व बढ़ा। जो आज भी प्रभावी है। कई राज्यों में आरक्षण 70 से 80% तक कर दिया गया। जिससे यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया। उच्चतम न्यायालय ने 1992 में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी।

वी पी सिंह के बाद 1991 में बनी काँग्रेस की पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव सरकार ने मण्डल कमीशन का लाभ प्रभावशाली एवं आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों तक सीमित न रहे इसके क्रीमीलेयर फॉर्मूला बनाया । मण्डल की रिपोर्ट केवल शिक्षक संस्थायों नौकरियों तक सीमित थी इसे पंचायतों एवं शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों के बीच लागू करने के लिए 73वां 74वां संविधान संशोधन करके महिलाओं और पिछड़ों को जनप्रतिनिधित्व का अधिकार देने का क्रांतिकारी कदम उठाया। इस संशोधन में पहली बार सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। आरक्षण 50% से अधिक न हो इसके लिए महिलाओं को आरक्षण में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसिचित जन जाति के 21% कुल आरक्षण में 7% दलित महिला, पिछड़ों के 27% में 9% पिछड़ी जाति की महिला और अनारक्षित 50% में 17% महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गये। इस प्रकार पंचायतों एवं शहरी निकायों में कुल 33% पद आरक्षित किए गये। जनगणना में केवल धर्म एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की गणना होती है। 73वां 74वां संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ों का आकड़ा नहीं था इसलिए उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1994 में पिछड़ी जाति का रेपिड सर्वे कराया। 1991 की जनसंख्या के आधार पर एस सी/एस टी एवं 1994 के रेपिड सर्वे के आधार पर पिछड़ों के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत एवं शहरी निकायों के सभी पदों पर चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसी के आधार पर 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2021 में त्रि-स्तरीय पंचायत के चुनाव कराये गये। शहरी निकायों के चुनाव 1995, 2000 में साथ में हुये लेकिन राजनीतिक कारणों से शहरी निकायों के चुनाव 2006, 2012 और 2017 में हुये। जबकि 2022 का शहरी निकाय चुनाव आरक्षण के विवाद में फंसा हुआ है।

**जनप्रतिनिधि एवं नौकरियों में एक ऐसा फार्मूला संवैधानिक दायरे में लेकर लागू करने की आवश्यकता है जिसमें एक बार आरक्षण का लाभ पाए परिवार को दूसरी बार आरक्षण तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक उस जाति के परिवार को लाभ नहीं मिल जाये। यह पहल एक दल या एक सरकार नहीं कर सकते इनके लिए सभी राजनीतिक दलों को एक साथ जुटकर आना होगा।**

योगी सरकार ने विवादों के चलते चुनाव को टाला और कोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जस्टिस जसवंत सैनी की अध्यक्षता में किया जिसमे हीरा ठाकुर और प्रभुनाथ चौहान को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा आयोग में 25 सदस्य भी नामित किया गए हैं। जिसे 3 माह में अपनी रिपोर्ट देनी है। रैपिडसर्वे के आधार पर ही सपा, बसपा और भाजपा तीनों सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराये गये हैं। काका कालेकर आयोग से लेकर मण्डल कमीशन, छेदी

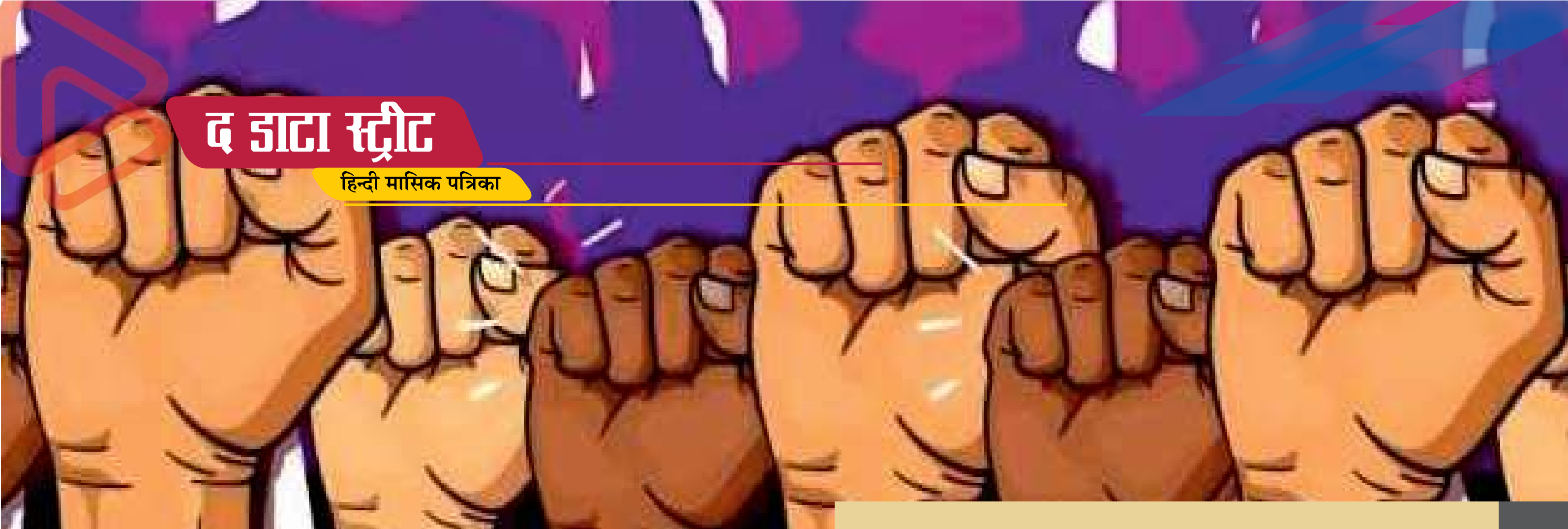

लाल साथी एवं 73वां 74वां संविधान संशोधन में आरक्षण को लेकर दिये गये जन प्रतिनिधि अधिकार एवं नौकरियों में अति पिछड़ों का हक नहीं मिला। इस समीकरण में यादव कुर्मी, लोध जातियों का वर्चस्व बढ़ता गया और जातियों के नाम पर नए-नए राजनीतिक दल उभरते गये। तत्कालीन मुख्यमंत्री राज नाथ सिंह ने अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए हुकुम सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सामाजिक न्याय समिति का गठन किया जिसमें रमा पति शास्त्री एवं दया राम पाल सदस्य थे।

सामाजिक न्याय समिति ने भी 21% अनुसूचित जातियों की आरक्षण में आरक्षण देने की सिफारिश की थी। अनुसूचित जाति की 66 जातियों को A और B कैटेगरी में विभाजित किया था। जिसमें चमार, धुसियाजाट व जिनकी आबादी दलितों में 55.70% थी उनका समूह ग में प्रतिनिधित्व 61.23% रहा। उन्हें 10% और दलितों की अन्य 65 जातियां जिनकी आबादी 44.30% है उन्हें 11% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की थी। उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या 0.21% रह गयी। इसके लिए अलग से 1% आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी।

सामाजिक न्याय समिति ने पिछड़ों की 79 जातियों को दिए जा रहे 27% आरक्षण को तीन श्रेणी (A B C) में विभाजित किया। इनमें यादव जिनकी आबादी पिछड़ों में 19.40% है। उन्हें 5% दूसरे श्रेणी में 8 जातियां (कुर्मी, पटेल, मल, सैंथवार, लोध, गुजर, गोसाई, गिरी, कम्बोज, स्वर्णकार और जाठ) जिनकी आबादी 18.91% है उन्हें 9% तथा अन्य 70 अति पिछड़ी जातियों को

**जनगणना में केवल धर्म एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की गणना होती है। 73वां 74वां संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ों का आकड़ा नहीं था इसलिए उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1994 में पिछड़ी जाति का रेपिडसर्वे कराया।**

जिनकी आबादी 61.69% है उन्हें 14% आरक्षण में आरक्षण देने की संस्तुति की थी। लेकिन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के तमाम प्रयास के बाद भी भाजपा के प्रभावशाली नेता ओम प्रकाश सिंह,राम कुमार वर्मा, विनय कटियार, कल्याण सहित तमाम विरोध के कारण लागू नहीं हो पाया यही नहीं सामाजिक न्याय समिति को जिन विभागों का मंत्रालय ओम प्रकाश सिंह, राम कुमार वर्मा व अन्य यादव जातियों के पास था उन्होंने अपने विभागों में कर्मचारियों की सूचनाएं देने में आना-कानी की और बहुत प्रयास के बाद मिली। जिसके कारण सामाजिक न्याय समिति को पिछड़ों के नेता अशोक यादव ने न्यायालय में चुनौती दी और जल्दबाजी में विसंगतियों से भरी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू करने से रोक दी गयी।

उपलब्ध आकड़ों के अनुसार 19.40% यादवों का प्रतिनिधित्व नौकरियों में 35.2% था। जबकि श्रेणी B की अन्य आठ जातियों जो कुर्मी पटेल लोध गोसाई, गुजर कम्बोज स्वर्णकार और जाठ जिनकी आबादी 18.91% उनकी समूह ग की नौकरियों में 29.11% प्रतिनिधित्व था जबकि 70 अन्य अति पिछड़ी जातियां जिनकी आबादी 61.69% उन्हें समूह ग में 37.12% प्रतिनिधित्व रहा।

# प्रदेश की अनुसूचित एवं अनुसूचित जन जातियां

| क्रम संख्या | जाति | परिवार रजिस्टर के आधार पर जनसँख्या 2001 | अनुसूचित जातियों में इस जाति का संख्या प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | चमार/धुसिया/जाटव | 19444012 | 55.70 |
| 1 | हेला | 32157 | 0.09 |
| 2 | धानुक | 548453 | 1.57 |
| 3 | बाल्मीकि | 1032055 | 2.96 |
| 4 | डोम | 126220 | 0.36 |
| 5 | बंगाली | 36421 | 0.10 |
| 6 | बहेलिया | 119893 | 0.34 |
| 7 | बसोड | 109599 | 0.31 |
| 8 | खरवार (बनवासी को छोड़कर) | 158294 | 0.45 |
| 9 | गोन्ड | 435802 | 1.25 |
| 10 | धरकार | 151955 | 0.44 |
| 11 | भुईया | 11007 | 0.03 |
| 12 | बादी | 8995 | 0.03 |
| 13 | महजबी | 10080 | 0.03 |
| 14 | काबड़िया | 23944 | 0.07 |
| 15 | बलहर | 3832 | 0.01 |
| 16 | बजनिया | 4863 | 0.01 |
| 17 | पंखा | 48142 | 0.14 |
| 18 | चोरो | 59083 | 0.17 |
| 19 | कोल | 387523 | 1.11 |
| 20 | बोरिया | 121443 | 0.35 |
| 21 | मुसहर | 259338 | 0.74 |
| 22 | बैगा | 39448 | 0.11 |
| 23 | परहिया | 47642 | 0.14 |
| 24 | सहरिया | 79286 | 0.23 |
| 25 | लालबेगी | 548 | 0.00 |
| 26 | घसिया | 11029 | 0.03 |
| 27 | खरैता | 670 | 0.00 |
| 28 | शिल्पकार | 21310 | 0.06 |
| 29 | सनोरिया | 348 | 0.0 |
| 30 | रावत | 45875 | 0.13 |
| 31 | चबगर | 2369 | 0.01 |
| 32 | भांतू | 6340 | 0.02 |

| क्रम संख्या | जाति | परिवार रजिस्टर के आधार पर जनसँख्या 2001 | अनुसूचित जातियों में इस जाति का संख्या प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 33 | सांसिया | 5797 | 0.02 |
| 34 | धांगर | 19725 | 0.06 |
| 35 | धीमर | 50154 | 0.14 |
| 36 | हरी | 345 | 0.0 |
| 37 | करवल | 5752 | 0.02 |
| 38 | तुरैहा | 34936 | 0.10 |
| 39 | हबुड़ा | 2498 | 0.01 |
| 40 | पतरी | 4326 | 0.01 |
| 41 | बलई | 8539 | 0.02 |
| 42 | बैसवार | 17497 | 0.05 |
| 43 | बनमानुष | 21677 | 0.06 |
| 44 | मझवार | 9914 | 0.03 |
| 45 | धरमी | 22946 | 0.07 |
| 46 | खटिक | 637356 | 1.83 |
| 47 | अगरिया | 26522 | 0.08 |
| 48 | बरवार | 15642 | 0.04 |
| 49 | बेड़िया | 57384 | 0.16 |
| 50 | धोबी | 2271459 | 6.51 |
| 51 | बावरिया | 7091 | 0.02 |
| 52 | भुईयार | 29315 | 0.08 |
| 53 | बधिक | 7314 | 0.02 |
| 54 | दुसाद | 246085 | 0.70 |
| 55 | खरोट | 13818 | 0.04 |
| 56 | कोरवा | 16543 | 0.05 |
| 57 | बाजगी | 1589 | 0.0 |
| 58 | कंजड़ | 73935 | 0.21 |
| 59 | बेलदार | 170411 | 0.49 |
| 60 | कलाबाज | 17593 | 0.05 |
| 61 | बांसफोर | 55.28 | 0.16 |
| 62 | ग्वाल | 21829 | 0.06 |
| 63 | नट | 211770 | 0.61 |
| 64 | कोरी | 1882710 | 5.39 |
| 65 | पासी, तरमाली | 5554190 | 15.91 |
| | | **15465654** | **44.30** |

# उत्तर प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. थारू | 2. बोक्सा | 3. भोटिया | 4. राजी | 5. जौसारी |

# प्रदेश की पिछड़ी जातियां

| क्रम संख्या | जाति | परिवार रजिस्टर के आधार पर जनसँख्या 2001 | अनुसूचित जातियों में इस जाति का संख्या प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | अहीर, ग्वाला, यादव, यदुवंशीय | 14677433 | 19.40 |
| | | **14677433** | **19.40** |
| 1 | सोनार, सुनार, स्वर्णकार | 412224 | 0.54 |
| 2 | जाट | 2726283 | 3.60 |
| 3 | कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मीमल्ल, कुर्मी सैंथवार | 5646569 | 7.46 |
| 4 | गिरि | 107278 | 0.14 |
| 5 | गूजर | 1291281 | 1.71 |
| 6 | गोसाई | 344784 | 0.46 |
| 7 | लोध, लोधी, लोधी, लोट, लोधी -राजपूत | 3706531 | 4.90 |
| 8 | कम्बोज | 70075 | 0.09 |
| | | **14305025** | **18.91** |

| क्रम संख्या | जाति | अनुसूचित जातियों में इस जाति का संख्या प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1 | अरख, अर्कवंशीय | 0.41 |
| 2 | काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य | 3.25 |
| 3 | कहार, कश्यप | 3.31 |
| 4 | केवट या मल्लाह, निषाद | 4.33 |
| 5 | किसान | 0.94 |
| 6 | कोइरी | 1.66 |
| 7 | कुम्हार, प्रजापति | 3.42 |
| 8 | कसगर | 0.03 |
| 9 | कुंजड़ा या राइन | 0.33 |
| 10 | गड़ेरिया, पाल, बघेल | 4.43 |
| 11 | गद्दी ,घोसी | 0.47 |
| 12 | चिकवा, कस्साव, चक, कुरैशी | 0.66 |
| 13 | छिपी, छिपा | 0.06 |
| 14 | जोगी | 0.33 |
| 15 | झोजा | 0.23 |
| 16 | डफाली | 0.23 |
| 17 | तमोली, बरई, चौरसिया | 0.71 |
| 18 | तेली, सामानी, रोजनगर, साहू, रौनियार, गंधी, अरार्क | 4.03 |
| 19 | दर्जी, इदरीसी, काकुस्थ | 1.01 |
| 20 | धीवर | 0.72 |
| 21 | नक्काल | 0.01 |
| 22 | नट (जो अनुसूचित जातियों श्रेणी में सम्मिलित न हो) | 0.19 |
| 23 | नायक | 0.07 |
| 24 | फकीर | 1.93 |
| 25 | बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी | 0.52 |
| 26 | बढ़ई-शैफी,विश्वकर्मा,पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान | 2.37 |
| 27 | बारी | 0.15 |
| 28 | बैरागी | 0.07 |
| 29 | बिंद | 0.87 |
| 30 | बियार | 0.14 |
| 31 | भर, राजभर | 2.44 |
| 32 | भुर्जा या भर भड़भूजा, भुज, कांदू, कसोधन | 1.43 |
| 33 | भटियारा | 0.06 |
| 34 | माली, सैनी | 1.44 |

| क्रम संख्या | जाति | अनुसूचित जातियों में इस जाति का संख्या प्रतिशत |
|---|---|---|
| 35 | स्वीपर, हलालखोर | 0.03 |
| 36 | लोहार, लोहार सैफी | 1.81 |
| 37 | लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया- चौहान | 2.33 |
| 38 | रंगरेज, रंगवा | 0.09 |
| 39 | मारछा | 0 |
| 40 | हलवाई, मोदनवाल | 0.37 |
| 41 | हज्जाम (नाई), सलमानी, सविता, श्रीवास | 3.01 |
| 42 | राय सिक्ख | 0.12 |
| 43 | सक्का-भिस्ती, भिस्ती-अब्बासी | 0.29 |
| 44 | धोबी | 0.48 |
| 45 | कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार | 0.05 |
| 46 | नानबाई | 0.01 |
| 47 | मीर शिकार | 0.03 |
| 48 | शेख सरवरी (पिराई) पीराही | 0.44 |
| 49 | मेव, मेवाती | 0.3 |
| 50 | कोष्टा/कोष्टी | 0 |
| 51 | रोड़ | 0.02 |
| 52 | खुमरा, संगतराश, हंसीरी | 0.01 |
| 53 | मोची | 0.02 |
| 54 | खागी | 0.22 |
| 55 | तंवर, सिंघड़िया | 0.02 |
| 56 | कतुआ | 0 |
| 57 | माहीगीर | 0.02 |
| 58 | दांगी | 0.01 |
| 59 | धाकड़ | 0 |
| 60 | गाड़ा | 0.24 |
| 61 | तंतवा | 0.01 |
| 62 | जोरिया | 0.01 |
| 63 | पतवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी | 0.07 |
| 64 | कलाल, कलवार, कलार | 0.57 |
| 65 | मनिहार, कचेर, लखेरा | 0.5 |
| 66 | मुराव या मुराई, मौर्य | 2 |
| 67 | मोमिन (अंसार) | 4.15 |
| 68 | मुस्लिम कायस्थ | 0.53 |
| 69 | मिरासी | 0.07 |
| 70 | नद्दाफ (धुनिया), मंसूरी, कण्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण) | 1.61 61.69 |
| 70 | नद्दाफ (धुनिया), मंसूरी, कण्डेरे, कडेरे, करण (कर्ण) | 1.61 |
| | | **61.69** |

**उत्तर प्रदेश की 66 दलित एवं 79 पिछड़ी जातियों में 18 अल्पसंख्यक जातियां हैं।**

# जातियों के नाम पर बने राजनीतिक दलों ने अपनी जातियों को ठगा

1989 के बाद देश की सियासत में मण्डल और कमंडल का प्रभाव बढ़ा। वी पी सिंह द्वारा मंडल कमीशन लागू करने के बाद देश में पिछड़ों का सियासत में हिस्सेदारी बढ़ी। ग्राम पंचायत से लेकर सांसद तक पदों पर पिछड़ों की संख्या अधिक हुई और नौकरियों में 27% से अधिक आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन यह सभी लाभ जाति की सियासत करने वाले दलित हो या पिछड़ें चुनिंदा परिवारों तक सीमित होकर रह गया। बिहार में पिछड़ों का सर्वाधिक लाभ लालू परिवार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर, केशव देव मौर्या आदि पिछड़ें परिवार तथा दलितों में बिहार में रामविलास उत्तर प्रदेश में मायावती तथा सरकारी नौकरियों में पिछड़ों व दलितों में चंद परिवारों ने लाभ उठाया है। इसीलिए आवश्यकता जातीय एवं आर्थिक गणना के साथ आरक्षण में आरक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि समाज के अंतिम व्यक्ति चाहे वह किसी वर्ग का क्यों न हो, लाभ मिल सके।

# रेवड़ी कल्चर

**गुजरात में भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व 4 हजार गांवों को मुफ्त वाई-फाई तथा गौ संरक्षण के लिए 500 करोड़ रूपये का एलान किया। इसके बाद भी मोदी को गुजराती अस्मिता का एहसास कराते हुए यह कहना पड़ा कि गुजराती मानुष कर्म प्रधान है और वह मुफ्त में कुछ नहीं लेता है।'**

इसके विपरीत राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दल तो इसके सारे मिथक ही तोड़ रहे है। देश और प्रदेशों के विकास कार्य, अवस्थापन सुविधाएं, रोजगार के कार्य पीछे छूटते जा रहे हैं और जनता को सीधे मिलने वाले लाभ की घोषणाएं पूरी चुनावी समीकरण को बदल दे रही है।

**◻ विजय शंकर पंकज**

प्रधानमंत्री की बड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर छोटे दलों के बिजली पानी की छूट ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप को सत्ता ही नहीं दिलायी बल्कि अन्य राज्यों में भी पैर पसारने का मौका दिया है। यही कारण है कि केवल 8 वर्ष की राजनीति में ही आप ने राष्ट्रीय दल का खिताब हासिल कर लिया है।

आप का मुफ्त बिजली एवं पानी की योजना दिल्ली में रिकार्ड विजय के बाद पंजाब में भी जीत हासिल करने में सफल रही। यही कारण रहा कि जब 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आप ने अपने वादों की सफलता की कहानी बताते हुए महिलाओं को एक हजार रुपये महीना देने का तीसरा वादा किया तो भारतीय जनता पार्टी की तीन दशक की सत्ता की चूले हिलने सी लगी। इससे बचने

के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने गृह प्रदेश की सत्ता बचाने के लिए पूरी अस्मिता दांव पर लगानी पड़ गयी। इससे बचने के लिए गुजरात में भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व 4 हजार गांवों को मुफ्त वाई-फाई तथा गौ संरक्षण के लिए 500 करोड़ रूपये का एलान किया। इसके बाद भी मोदी को गुजराती अस्मिता का एहसास कराते हुए यह कहना पड़ा कि गुजराती मानुष कर्म प्रधान है और वह मुफ्त में कुछ नहीं लेता है।'

गुजरात के ही चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'रेवड़ी संस्कृति की बात उठायी। मोदी ने ही कहा कि चुनावी वादों में किये जाने वाले ऐसी रेवड़ी बांटने की राजनीति देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करेगी। गुजरात से पहले हुए हिमाचल प्रदेश के चुनाव ने कांग्रेस के मात्र एक नारे से भाजपा की पूरी रणनीति को ही झकझोर कर रख दिया। आप के मुफ्त बिजली पानी की घोषणा से घबड़ाई भाजपा ने हिमाचल में चुनाव पूर्व ही यह योजना लागू कर दी। इसके विरुद्ध कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा कर दी। हिमाचल के कम आबादी वाले राज्य में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी है। इसका प्रभाव यह रहा कि प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा नेता अपनी तमाम कार्यकारी

**भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व 4 हजार गांवों को मुफ्त वाई-फाई तथा गौ संरक्षण के लिए 500 करोड़ रूपये का एलान किया। आप के मुफ्त बिजली पानी की घोषणा से घबड़ाई भाजपा ने हिमाचल में चुनाव पूर्व ही यह योजना लागू कर दी।**

योजनाओं को घोषणा और उनके अनुपालन का गुणगान करते रहे परन्तु कांग्रेस की केवल पुरानी पेंशन योजना इन पर भारी पड़ी और भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी।

# प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाएं

## उज्ज्वला योजना-

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनकल्याण के नाम पर कई ऐसी योजनाओं की घोषणा की जिसके लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित कर भाजपा के लिए वोट बैंक बन गये। इसमें **"उज्जवला योजना"** के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेन्डर दिये गये। इससे 9 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई। इसकी लंबी चर्चा हुई परन्तु जब गैस सिलेन्डर के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गये तो यह योजना फ्लाप हो गयी। महंगे गैस सिलेन्डर के कारण मुफ्त सिलेन्डर मिलने के बाद लगभग 3 करोड़ लोगो ने एक ही बार गैस भरवाया जबकि 2.25 करोड़ लोगो ने एक बार भी सिलेन्डर नही भरवाया। मुफ्त गैस सिलेण्डर की आड़ में केन्द्र सरकार ने रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी जिससे सरकार को लगभग 24 हजार करोड़ रूपये की बचत हुई जबकि उज्जवला योजना पर मुफ्त गैस सिलेन्डर देने पर ही सरकार ने मात्र 8000 करोड रूपये तीन साल में खर्च किये। इस प्रकार मुफ्त सिलेन्डर देने की योजना बनाकर सरकार ने जहां वाहवाही लूटी, गैस सब्सिडी बंद कर दो तिहाई लगभग 24 हजार करोड़ रूपये की बचत की ली।

इस प्रकार भारत सरकार का अर्थ तंत्र मुफ्त की वाहवाही योजना के बाद भी फायदेमंद रही।

## किसान सम्मान निधि -

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को लागू हुई। इस योजना के तहत प्रारम्भ में 2 हेक्टेयर की कृषि भूमि वाले सभी छोटे एवं सीमान्त किसानों को एक वर्ष की तीन किस्तों में 6 हजार रूपये की धनराशि दी जाती है। बाद में इसमें संशोधन कर उन सभी किसानों को शामिल किया गया जिनकी पेंशन या आय 10 हजार रूपये अथवा उससे कम हो। सरकारी आकड़ो के अनुसार इसके लगभग 14 करोड़ किसान लाभार्थी है। सरकार ने 2020-21 में किसान सम्मान निधि के तहत 75 हजार करोड़ रूपये जारी किये परन्तु तमाम जांचो के बाद आय स्रोतों के आधार पर कुछ को छंटनी होने के बाद वर्ष 2021-22 में इसमें 10 हजार करोड़ की बचत हुई।

## प्रधानमंत्री आवास योजना-

प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा 25 जून 2015 को की गयी। इसके तहत गरीब परिवार के

महिलाओं को सस्ते दरों पर पक्के सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना था। इसके तहत 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है। कई राज्य सरकारें अपने हिस्से की धनराशि मुहैया नहीं करा सकी जिससे यह योजना खींचतान में फंसी रही। इसके तहत ढाई से चार लाख के आवास बनते है। अब तक इस योजना तहत 70 लाख बन चुने है जबकि अगले वित्तीय वर्ष में 80 लाख बनाने का लक्ष्य है।

## प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना -

देश में करोना काल में अप्रैल 2020 में गरीबों को मुफ्त राशन दिये जाने की प्रधानमंत्री ने की थी। इसके तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। इस पर केन्द्र सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रूपये खर्च किये। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना लोन स्कीम भी लागू की गयी थी। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने सैनिकों की बहुप्रतिक्षित'वन रैंक वन पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान कार्ड भी लागू की गयी। भारत सरकार अभी तक विभिन्न चरणों में लगभग 220 कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की।

## भारतीय राजनीति में चुनावी रेवड़ी का इतिहास-

भारतीय राजनीति में चुनावी रेवड़ी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। इसकी शुरूआत दक्षिण भारत के तत्कालीन राज्य मद्रास स्टेट (वर्तमान तमिलनाडू) से हुई। उस समय मद्रास स्टेट के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री कामराज ने 1954 के विधानसभा चुनाव में मुफ्त शिक्षा तथा छात्रों को मुफ्त भोजन की घोषणा की। कामराज प्लान 1963 तक चला। 1967 में डीएमके के फाउन्डर अध्यक्ष अन्ना दुरई ने 45 किलो चावल देने की घोषणा की। कामराज की ही तरह से एमजी रामचन्द्रन ने भी 1982 में छात्रों को मुफ्त भोजन देने की घोषणा की। 1980 में प्रदेश में एनटी रामराव ने 2 रूपये किलो चावल देने की घोषणा

की। इसके बाद दक्षिण भारतीय राज्यों में हर चुनाव में रेवड़ी घोषणाएं होने की परम्परा बन गयी। एआईएडीएमके नेता जेजयललिता ने मुफ्त साड़ी, प्रेशरकुकर, टेलीविजन और वाशिंग मशीन देने की घोषणा की। जयललिता की अम्मा रसोई की राज्य में बड़ी चर्चा रही। पहली बार पंजाब में 1990 में अकाली दल ने किसानों को मुक्ति देने की घोषणा की। 2006 में डीएमके ने वोटर्स को कलर टीवी देने का वादा किया। इसके साथ ही तमिलनाडू में कई पार्टियां गैस स्टोव, कैस, जमीन और मैटरनिटी सहायता आदि तमाम चीजे देने की घोषणा करती रही।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते मुलायम सिंह यादव ने 2004 में 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत की। इसके साथ ही लड़कियो को साइकिल भी दी गयी। इसके बाद भी 2007 का चुनाव मुलायम सिंह यादव हार गये। वर्ष 2012 में जब सपा के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो बेरोजगारी भत्ता 1000 रूपये कर दिया गया परन्तु यह लंबा नहीं चल सका। अखिलेश ने छात्रों को लैपटाप भी बांटा। सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों तथा शिथिलता के बाद भी 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दोबारा सत्ता में आ गयी। राज्यों के बाद पहली बार केन्द्र सरकार का किसानों को यह सीधा लाभ देने की योजना थी। इसके पूर्व पंजाब में किसानों की कर्जमाफी कारगर साबित हुई थी। कांग्रेस की ही तर्ज पर यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसान कर्जमाफी की घोषणा की।

चुनावी घोषणा में दिल्ली की आप पार्टी सब पर भारी रही। 2015 के दिल्ली राज्य के चुनाव में आप ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की घोषणा कर एतिहासिक जीत दर्ज की। इसमें कांग्रेस का सफाया हो गया तथा भाजपा मुश्किल से 3 सीटे जीत पायी। आप का यह प्रयोग 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कारगर हुआ। आप हर राज्य के चुनाव में अपनी इस घोषणा को लगातार दोहरा रही है। इसके अलावा कई राज्यों में भी कई चुनावी घोषणाएं हुई जो सरकार बनने पर कारगर साबित नहीं हुई। राजस्थान के 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3500 रूपये माहवार बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी जो सरकार बनने के बाद ठंढे बस्ते में चली गयी। इसी प्रकार 2018 के मध्यप्रदेश के चुनाव में भाजपा ने 75 प्रतिशत अंक पाने

**मुलायम सिंह यादव ने 2004 में 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत की, साथ ही लड़कियो को साइकिल भी दी गयी। इसके बाद भी 2007 का चुनाव मुलायम सिंह यादव हार गये। वर्ष 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो बेरोजगारी भत्ता 1000 रूपये कर दिया गया परन्तु यह लंबा नहीं चल सका। अखिलेश ने छात्रों को लैपटाप भी बांटा।**

वाले छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 10 लाख बेरोजगार युवाओं को मासिक अनुदान, किसानों की कर्ज माफी तथा बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी। ओड़ीसा में किसानों को 10 हजार रूपये तथा भूमिहीनों को 12 हजार रूपये मासिक देने का वादा किया गया। बिहार विधानसभा के 2020 के चुनाव में भाजपा ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की। इसी प्रकार 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कालेज जाने वाली हर लड़की को स्कूटी देने का वादा किया था परन्तु सरकार बनने के बाद अभी तक जुम्बिश तक नही हुई।

# अन्य राज्यों में चल रही महत्वपूर्ण योजनाएं

## पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाएं

पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। कुछ नाम हैं, कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मीर भंडार, युवस्री, शिक्षाश्री, जय बंगला, लोकप्रसार, निजो गृह निजो भूमि, स्वास्थ्य साथी, गतिधारा, गीतांजलि, खाद्या साथी, साबूज साथी, सबुजश्री, सुफलबांग्ला, शिशु साथी, सबला आदि।

### एक्यश्रीछात्रवृत्ति योजना

पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2019-20 से राज्य के बजट से पूरी तरह से वित्त पोषित होगी।

### गतिधारा योजना

WBTIDCL इस परियोजना का सक्रिय एजेंट है। वाणिज्यिक कारों के मामले में राज्य सरकार कार की कीमत का 30% या अधिकतम 1 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी।

### गीतांजलि आवास योजना

मैदानी क्षेत्र में 70 हजार प्रति मकान एवं रु. इस परियोजना गीतांजलि के तहत पहाड़ी क्षेत्र में और सुंदरबन क्षेत्र में भी प्रति घर 75 हजार राज्य सरकार प्रदान कर रही है।

### जय बांग्ला योजना, 2020

60 वर्ष से अधिक आयु के सभी अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति योजना के तहत पात्र हैं और रुपये की पेंशन प्राप्त करेंगे। 1,000 प्रति माह।

### कन्याश्रीप्रकल्प

एक अविवाहित बालिका जो 13 से 18 वर्ष की है और आठवीं/नौवीं/ग्यारहवीं/बारहवीं कक्षा में पढ़ती है, को 750/- रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। यदि उसके परिवार की वार्षिक आय रु. 1.2 लाखसे कम है।

### कर्म साथी प्रकल्प

इच्छुक या भावी उद्यमियों की मदद के लिए नए दरवाजे खोलकर होनहार युवाओं के लिए रोजगार सृजन और उन्हें आत्म निर्भर बनाना।

### कृषक बंधु योजना कृषक बंधु (सुनिश्चित आय और मृत्यु लाभ) योजना

जिसके तहत रिकॉर्डेड भागचासी (शेयर क्रॉपर) सहित प्रत्येक किसान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

### खाद्य साथी योजना

खाद्य साथी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों/फुटपाथ पर रहने वालों, सूखा प्रभावित लोगों आदि के भोजन की आपूर्ति करके भोजन और पोषण सुनिश्चित करना है।

## लक्ष्मीर भंडार प्रकल्प

राज्य के सभी परिवारों की महिला सदस्यों को उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सुनिश्चित मासिक आय प्रदान करना।

## मानविक पेंशन योजना, 2018

यह 50% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए लागू है और विकलांग व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000.00 (रुपये एक लाख) प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं है।

## निजो गृह निजो भूमि

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवासहीन खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और मछुआरों के प्रति परिवार को पांच डिसमिल भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाता है।

## एलआईजी/एमआईजी के लिए निज श्री आवास योजना

पश्चिम बंगाल सरकार निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) से संबंधित सभी लोगों को एक 'बाशा' (घर) प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

## "प्रचेस्टा" (প্রচেষ্টা)

COVID-19 के प्रकोप के कारण अत्यधिक संकट में रहने वाले मजदूर / दैनिक वेतन भोगी / श्रमिक को कुछ वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए।

## पाठसाथी

पाठसाथी में प्रत्येक 50 किमी पर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कें पर एक छत के नीचे पे एंड यूज शौचालय, प्रतीक्षालय, रैन बसेरा और रेस्तरां शामिल हैं।

## पारिजयी सहाय

प्रवासी श्रमिकों को सूखे राशन और अन्य लाभों के रूप में कुछ राहत प्रदान करने के लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

## पर्यटन सहायता प्रकल्प

राज्यपाल पश्चिम बंगाल में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र

के लिए एक राहत योजना के रूप में "पर्यटन सहायता प्रकल्प" (नाम सांकेतिक है) योजना किया हैं।

## रूपश्री प्रकल्प

पश्चिम बंगाल सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को विवाह हेतु 25,000/- रुपये की राशि दी जायेगी। समर्थन रुपये की एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी।

## स्नेहालयप्रकल्प

पश्चिम बंगाल में अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं रखने वाले लोगों को पक्का आवास प्रदान करना।

## सामाजिक सुरक्षा योजना

असंगठित श्रमिकों के लिए एक नई और समेकित सामाजिक सुरक्षा योजना, अर्थात् सामाजिक सुरक्षा योजना, 2017।

## शिशु साथी योजना

शिशु साथी योजना 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए है, जिन्हें दिल की

सर्जरी की आवश्यकता है, चाहे माता-पिता कितने भी अमीर या गरीब क्यों न हों।

## किशोरियों के लिए सबला योजना

सबला का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, गृह कौशल, जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल का उन्नयन करके सशक्त बनाना है।

## स्वास्थ्य साथी योजना

संविदा/आकस्मिक/दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए "स्वास्थ्य साथी"।

## उत्कर्ष बांग्ला

पश्चिम बंगाल राज्य के निवासियों को वेतन/स्वरोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संपूर्ण गैर-संस्थागत, गैर-परियोजना मोड, अल्पावधि कौशल विकास हस्तक्षेप के लिए एक प्रमुख योजना।

## अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम

स्व-रोजगार उद्यमों के लिए सॉफ्ट लोन, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऋण, वजीफा और छात्रवृत्ति, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आदि प्रदान करना।

## युवश्री (युवा उत्साह प्रकल्प)

योजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता और कौशल में वृद्धि के लिए रोजगार सहायता प्रदान करना है।

# दिल्ली सरकार की योजनाएं

दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर राज्य के सभी नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओ को शुरू किया है। जिन योजनाओं का लाभ राज्य के सभी लोगो को मिलता है।

## मुफ्त बिजली योजना

200 यूनिट बिजली का प्रयोग करने पर होने वाले लाभ-इस योजना के माध्यम से 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले परिवारो को बिजली के बिल का भुगतान नही करना पड़ेगा।

## मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना

दिल्ली सरकार द्वारा राज्य के सभी नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए तीर्थ यात्रा योजना 2022 को शुरू किया है इस योजना का लाभ दिल्ली के सभी वरिष्ठ नागरिक ले सकते है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और वे गरीब परिवार के है ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में धार्मिक स्थलों की तीर्थ यात्रा नि:शुल्क सुविधा प्रदान करेगी।

## मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत एमएसपी रेट सरकार द्वारा प्रस्तुत एमएसपी रेट गेंहू के मामले मे 776 रु प्रति किवंटल व धान मे 897 रु प्रति किवंटल से काफी अधिक है । इस के मुताबिक एमएसपी से सरकार पर करीब 100 करोड़ रु का अधिक भार पड़ेगा ।

## दिल्ली मुख्यमंत्री आवास योजना

भारत की राष्ट्रीय राजधानी की राज्य सरकार ने

झग्गी झोपडी मे रहने वाले 65,000 परिवारों को परिवारों को प्रमाण पत्र वितरित किए है । उन सभी परिवारों को जल्द ही पक्के मकान उपलब्ध करवाया जाएगा।

## मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना

इस योजना का उदेश्य घर मालिको को किरायेदारों से अधिक पैसे लेने से रोकता है । एक बार प्री पेड बिजली मीटर योजना प्रारम्भ हो जाने के बाद किरायेदारों को बिजली सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा

## दिल्ली पानी बिल माफी योजना

इस योजना के तहत दिल्ली के लोग जो फंक्शनल मीटर के जरिए अपने बिल का भुगतान कर रहे है। उनको विशेष लाभ दिया जा रहा है । इस योजना के अनुसार उन लोगो का सारा बकाया माफ कर दिया जाता है। इस योजना के तहत E, F, G, H कालोनियों मे रहने वाले नागरिकों को 100% प्रिंसिपलअमाउंट माफ कर दिया जाता है। इस योजना से दिल्ली मे रहने वाले लोगो को जल के बिल मे भारी छूट प्रदान की जाएगी ।

## लाड़ली योजना

इस लाड़ली योजना कन्या के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई पूरी होने के लिए दिल्ली सरकार उन्हे

आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी । जिससे बेटिया उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन मे आत्म निर्भर बन पाएगी। इस योजना मे दिए जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 5000 रु से लेकर 11000 रु तक की सीमा रखी गई है ।

## मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना

इस योजना मे 9वी एवं 10वी के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कारवाना। 9वी 10वी के छात्र जिन्होने पिछली कक्षा मे कम से कम 50% प्राप्त किए हो उनको उस साल 5,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। 11वी 12वी के जो छात्रो के पिछले कक्षा मे कम से कम 60% अंक प्राप्त किए होगे उनको वार्षिक 10 हजार रु छात्रवर्ती देने की घोषणा की गई है।

## दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी

राज्य मे प्रदूषण कम करने व रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के तहत इलेक्टोनिक व्हिकल खरीदने के लिए 30,000 से लेकर

1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि सरकार के दुवारा प्रदान किया जाता है।

## मजदूर भत्ता सहायता योजना

इस योजना मे मजदूरो को आर्थिक सहायता के 5,000 रु मदद दी जाएगी यह दिल्ली सरकार कल्यांणकारी योजना मे से एक है।

# केरल सरकार की मुख्य योजना

## केरल अथिजीवनम केरलियम योजना

केरल अथिजीवनम केरलियम योजना की घोषणा मुख्यमंत्री पिनाराईविजयन द्वारा 27 अगस्त 2020 को की गई है। इस योजना में, केरल सरकार चालू वित्त वर्ष में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। यह योजना राज्य सरकार के मुख्यमंत्री स्थानीय रोजगार आश्वासन कार्यक्रम (एलएएपी) के तहत लागू की जाएगी।

## केरल गौ समृद्धि प्लस स्कीम

गौसमृद्धि प्लस योजना में सामान्य वर्ग के किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। एससी और एसटीवर्ग के तहत आने वाले लोगों के लिए यह 70% सब्सिडी होगी। गौसमृद्धि योजना के लिए बीमा कवरेज 1 वर्ष और 3 वर्ष के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत 2 लाख मृत्यु बीमा भी प्रदान किया जाएगा।

## विकलांगता छात्रवृत्ति योजना

विकलांग छात्रों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए विकलांग छात्र छात्रवृत्ति योजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। विकलांगता छात्रवृत्ति योजना वाले केरल के छात्रों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विकलांग छात्र को पेशेवर या पीजी पाठ्यक्रमों तक पहली मानक से 500 रुपये प्रति माह से 2900 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

## जीवन-आवास योजना

2 लाख बेघर या बिना भूमि वाले परिवारों को घर उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य उन लोगों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। जिनके पास अपना घर या जमीन नहीं है।

## थालोलम योजना

इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नि: शुल्क उपचारप्रदान करना है जो किडनी रोग, हृदय संबंधी रोग, सेरेब्रलपाल्सी, ब्रिटलबोनडिजिस, हेमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आर्थोपेडिक विकृतिऔर अन्य न्यूरो-डिवेलपमेंट डिसएबिलिटी, कॉनजैनीटल से पीड़ित हैं।

## भूख मुक्त शहर परियोजना

गरीब लोगों के लिए भूख से मुक्त शहर परियोजना शुरू की है।यह परियोजना शुरू में कोझीकोड शहर में शुरू हुई और सरकार ने आधुनिक रसोईघर स्थापित करने के लिए 65 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च की है। आधुनिक रसोई में एक समय में 350 व्यक्तियों की बैठने की जगह है।

## केरल में प्रवासी बीमा योजना

इस योजना में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के उत्तर-पूर्वराज्यों से केरला में 25 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक शामिल हैं।

## वयोमीश्रम योजना

इस परियोजना के अंतर्गत सरकार मुख्य रूप से बुजुर्ग लोगों के लिए मोबाइल क्लीनिक, पैलिएटिव देखभाल और सहायता डेस्क सेवाओं के माध्यम से मुफ्त दवाएं प्रदान करती है यह परियोजना सबसे पहले कोलाम और त्रिवेंद्रम निगम में शुरूकी गई है।

## शिक्षा सहायता योजना

5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए और1और 5 वीं कक्षा के बीच पढने वालों को 300 रुपये प्रति माह मिलेगा।6वीं और 10 वीं कक्षा के बीच पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। 11 वीं और 12 वीं कक्षा में पढ़ाई वाले बच्चों को प्रति माह 750 रुपये मिलेंगे। 1000 रुपये प्रति माह: बच्चों को जो डिग्री के लिए या ऊपर पढ़ रहे हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा।

## स्नेहाश्वन्मम स्कीम

एंडोसेल्फान पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए केरल सरकार (सामाजिकन्याय विभाग) द्वारा स्नेहाश्वन्मम योजना शुरू की गई है इस योजना के तहतसरकार एन्डोसल्फानपीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैपीड़ितों को 2000/ - रु की वित्तीय सहायता दी जाती है।

# तमिलनाडु सरकार की मुख्य योजना

## तमिलनाडु फ्री लैपटॉप योजना

उन छात्रों के लिए शुरू की गई है। जिन्होंने हाल ही में 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है इस योजना के तहत सरकार लड़कियों को लैपटाप बांटने जा रही है।

## तमिलनाडु युवा अधिवक्ता मासिक भत्ता योजना

युवा वकीलों की सहायताके लिए लायर्सस्टाइपेंड स्कीम लॉन्च की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने नौ युवा वकीलों को दो साल के लिए 3,000 प्रति माह दर स्टाइपेंड प्रदान किया।

## तमिलनाडु फार्म ऋण माफी योजना

तमिलनाडु किसान ऋण माफी योजना 13 फरवरी 2021 को 12,110 करोड़ रुपये के 16 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है।

## तमिलनाडु नान मधुबन योजना

तमिलनाडु के लगभग 10 लाख छात्रों को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इस कार्यक्रम के तहत उनके कौशल और प्रतिभा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें उन्हें ज्ञान विकसित करने और शैक्षिक पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

## तमिलनाडु सरकार पोंगल उपहार योजना

'पोंगल' योजना के तहत राज्य में प्रत्येक परिवार को 1,000 रुपये के साथ एककिलो कच्चा चावल और चीनी दी जाएगी। यह भी घोषणा की गई है कि राज्य में रहने वाले श्रीलंकाई तमिल परिवार भी पोंगल उपहार का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

## तमिलनाडु कन्या विवाह योजना

अपनी बेटियों की शादी करवाने और गरीब लड़कियों की शैक्षिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए गरीब माता-पिता को सहायता प्रदान करना। 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता और, 8 ग्राम सोने का सिक्का (22 कैरेट) थिरुमंगलम बनाने के लिए प्रदान किया जाता है। 50,000 वित्तीय सहायता और 23.05.2016 की तारीख से,

थिरुमंगलम बनाने के लिए 8 ग्राम सोने का सिक्का (22 कैरेट) प्रदान किया जाता है।

### तमिलनाडु स्वास्थ्य रोग योजना

तमिलनाडु सरकार ने गैर-संचारी रोगों के इलाज के लिए मरीजों को अस्पतालों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से एक 'डोर स्टेप हेल्थ केयर' स्कीम'मक्कलाईथेडीमारुथुवम' शुरू करने की योजना बनाई है।सात जिलों में योजना को लागू करने के लिए 1,264 स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 50 फिजियोथेरेपिस्ट और 50 नर्सों को नियुक्त किया गया है।

### तमिलनाडु मध्य परिवार समृद्धि योजना

इस योजना के तहत हर परिवार को सालाना 6000 रूपए दिए जायेंगे। इस योजना में 6000 रूपए जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

### तमिलनाडुराइस कार्ड योजना

तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्योहार के दौरान राज्य के राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सभी राशन कार्ड धारकों को एक किलो चीनी और चावल फ्री में दिया जाएगा।

## आंध्र प्रदेश सरकारी योजना

### वाईएसआर संपूर्ण पोषणाप्लस स्कीम

इस योजना में, राज्य सरकार आदिवासी गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करेगी। यह वाईएसआर संपोरणपोशन प्लस योजना राज्य के 77 आदिवासी मंडलों में लागू की जाएगी। शेष मैदानी क्षेत्रों के लिए एक और वाईएसआर सम्पूर्ण पोषण योजना भी लागू की जाएगी। इन दोनों योजनाओं के लिए राज्य सरकार लगभग 1863 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

### आंध्र प्रदेश वाईएसआरचेयुत्था योजना

इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग औरअल्पसंख्यक समुदाय की 23 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। राज्य सरकार अपनी इस कल्याणकारी स्कीम पर 17,000 कोरड़ रुपये खर्च कर रही है।

### आंध्र प्रदेश जगन्ना विद्या कनुका योजना

राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 वीं के प्रत्येक छात्र को तीन जोड़ी वर्दी, पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, बेल्ट और एक स्कूल बैग प्रदान करेगी। योजना के तहत राज्य भर में कुल 43 लाख छात्रों को विद्या कनुकाकिट दी जाएगी।

### बीमा योजना

परिवार के सदस्यों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'YSR बीमा' योजना शुरू की है। सफेद राशन कार्ड वाले सभी परिवार वाईएसआर बीमा योजना के लिए पात्र होंगे।18-50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता: 5 लाख रु.। 51-70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए आकस्मिक मृत्यु और स्थायी विकलांगता: 3 लाख रु.। सामान्य मृत्यु के मामले (18-50 वर्ष): 2 लाख रु.। दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (18-70 वर्ष): 1.5 लाख रु।

### वाहना मित्रा स्कीम

देश के इतिहास में पहली बार ऑटो, कैब और कार चालकों को हर साल 10 हजार रुपये मुफ्त में दिये जाएंगे।

### सम्पूर्ण पोषण/सम्पूर्ण पोषण प्लस योजना

राज्य सरकार आदिवासी गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और कम आय वाले परिवारों के बच्चों को स्वस्थ भोजन देने के लिए इस प्रोग्राम को लागू करेगी। यह प्रोग्राम पूरे राज्य में 55,607 आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा, जिससे कुल 30 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

### आंध्र प्रदेश रायथू भरोसा स्कीम

सरकार किसानो को 12500 रु तक की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में माध्यम से (बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए) निवेश के रूप में प्रदान करेगी।

### आंध्र प्रदेश अम्मा वोडी योजना शिक्षा

अम्मा वोडी योजना में सालाना 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता दी जाएगी. स्कीम में राज्य की लगभग 43 लाख माताओं के खाते में यह राशि 82 लाख बच्चों के फायदे के लिए डाली जाएगी। यह प्रोत्साहन उन्हें कई संस्थानों में अपने बच्चे पहली से बारहवीं तक के बच्चों को शिक्षित करने में सक्षम करेगा।

### आंध्र प्रदेश जगन्नाणचेदोडु' योजना

राज्य सरकार नई ब्राह्मणों (बालों की ड्रेसिंग), रंगरेज (दर्जी) और रजाका (लॉन्ड्री) को वित्तीय सहायता (10,000 प्रदान कर रही है।

### आंध्र प्रदेश जगनन्नाजीवा क्रांति योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश की गरीब महिलाओं को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना है। राज्य सरकार तीन किश्तों या चरणों में कुल 249151 भेड़/बकरी का वितरण करेगी। इस योजना का पहला चरण मार्च 2021 में पहले ही पूरा हो चुका है।

## तेलंगाना सरकार की योजनाएं

### एकल महिला पेंशन योजना

तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य भर में 'एकल महिला पेंशन योजना' शुरू की। इस योजना के तहत राज्य की एकल महिलाओं को,1,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।

### कल्याण लक्ष्मी योजना

इस योजना के तहत राज्य सरकार तेलंगाना में लड़की की शादी के समय दुल्हन के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार 51000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

### तेलंगाना बेरोजगारी भत्ता योजना

इस योजना का नाम तेलंगाना बेरोजगारी भत्ता योजना रखा गया है। इस योजना को सरकार ने अपने सरकार के 2019-20 के बजट में लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार बेरोजगार युवाओ को हर महीने 3,000/ रूपये की धनराशि प्रदान करेगी।

### तेलंगाना रायथूभीमापथाकम

राज्य सरकार किसानों को रबी और खरीफ सीजन के लिए साल में दो बार बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य सामान खरीद के लिए प्रति एकड़ 5-5 हजार रुपये प्रदान करती है।

### टी एस ईपास स्कालरशिप

तेलंगाना छात्रवृत्ति शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य योग्य छात्रों को बिना किसी वित्तीय बाधा के अपने सपनों की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

# राजनीतिक गलियारा

□ विजय शंकर पंकज

**देश के राजनीतिक गलियारे में वर्ष 2023 की शुरुआत से ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। सभी राजनीतिक दलों के कार्यक्रम रोज चुनाव को देखकर ही बनाये जा रहे हैं। इसी क्रम में गठबंधन से लेकर के संगठन को सक्रिय और कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत के फंडे बताये जा रहे हैं। इस कार्य में अब भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां अन्य दलों से काफी आगे हैं। कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल का संकेत अवश्य दिया है लेकिन परन्तु उसका अब भी पूरा फोकस राहुल गाँधी के भारत जोड़ों अभियान पर ही लगा हुआ है। क्षेत्रीय दलों में टीआरएस अपनी ताकत केंद्र में बढ़ाने के लिए छटपटा रही है तो बंगाल से ममता और बिहार से राजद एवं जेडीयू की जोड़ी कसमसा रही है।**

## भाजपा- संगठन की मजबूती और मोदी का चेहरा

देश के अन्य प्रतिद्वंदी दलों के तुलना में भाजपा अब भी संगठनात्मक रूप से बहुत आगे है। वर्तमान में केवल भाजपा को ही कहा जा सकता है कि कश्मीर से केरल और गुजरात से असम तक देश के हर हिस्से में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा है। दक्षिण के कुछ राज्यों में भाजपा को भले ही चुनावी जीत न मिली हो परन्तु पार्टी ने अपने संगठन को तैयार करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है।

हिन्दुत्व की राजनीति पर फोकस करने के बाद भाजपा ने अपने संगठन की बनावट में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी ने अंशकालिक तौर पर बेरोजगार तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं की एक बड़ी टीम संगठन के कार्यों में लगा रखी है। ऐसे युवकों को पार्टी की तरफ से प्रति माह कुछ सहायता धनराशि मानदेह के नाम पर भी दी जाती है। भाजपा ने यह प्रयोग संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले खर्च "व्यय पत्रक" को ही आधार माना है। भाजपा संगठन में ऐसे लाखों कार्यकर्ता गाँव से लेकर शहर तक जुड़े हैं जो पार्टी की नीतियों का सोशल मीडिया

के माध्यम से प्रचार प्रसार के साथ ही विपक्षी दलों पर प्रहार करने से भी नहीं चूकते। हालांकि राष्ट्रीय मुख्यालय से लेकर सभी राज्यों में भाजपा का सोशल मीडिया सेल गठित है। जिसमें 10 से लेकर 100 तक कर्मचारी है। जिन्हें प्रतिमाह वेतनमान दिया जाता है। जिलों एवं छोटे शहरों और गावों में अंशकालीन कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए सहायता दी जाती है। इसके साथ ही भाजपा पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सक्रीय एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं के भाग दौड़ और जनसम्पर्क के लिए साइकिल और मोटर साइकिल की व्यवस्था करती है।

संगठन के अलावा भाजपा नेतृत्व अब भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और जनता में उनकी स्वीकारता को अब भी अपना सबसे सशक्त हथियार मानती है। यह राजनीतिक सच्चाई है कि किसी अन्य नेता की मोदी जैसी स्वीकारता नहीं है। इसके साथ ही भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक चर्चित नेताओं की एक लम्बी श्रृंखला है। यही कारण है कि चुनावी माहौल में भाजपा नेताओं की टीम अन्य दलों पर भारी पड़ती है।

## कांग्रेस - राहुल की पदयात्रा और संगठन में बदलाव

दशकों बाद कांग्रेस ने नेहरू परिवार से इतर संगठन की बाग़ डोर दक्षिण भारत के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को सौप कर बदलाव का संकेत दिया है। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कांग्रेस ने दलित वर्ग में जहाँ अपनी पैठ बनाने और सहानुभूति जताते की कोशिश की है। वहीं राज्य और जिला स्तर पर भी बदलाव का संकेत दिया है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल के जो कयास लगाए जा रहे थे वह अभी तक मंद पड़ा हुआ है। देश की राजनीति में भाजपा के बाद कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसकी पहचान पूरे देश में है और उसके नेता और कार्यकर्ता हर जगह दिखाई देते है। कांग्रेस की अंदुरुनी उहापोह एवं खींच तान के कारण कई बड़े नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव न करा के दिल्ली दरबार से राज्यों में नेता थोपे जाने के कारण भी संगठन को क्षति पहुंची है। पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और गणेश परिक्रमा करने वालों को पदाधिकारी बनाने से संगठन की स्थिति लगातार कमजोर होती गयी। अब भी यह रवैया जारी है।

उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस ने कई प्रयोग किये परन्तु असफल साबित हुए। उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल गुजरात आदि में कांग्रेस कई दशकों से सत्ता से बाहर है। राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थितियां अनुकूल है तो यहाँ से स्थानीय नेताओं के बढ़ते संघर्ष ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर भारत के राज्यों जब तक कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर क्षेत्रीय नेताओं को प्रभावी नहीं बनायेगी तब तक केंद्रीय सत्ता हासिल करना आसान नहीं होगा। दक्षिण भारत के राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत हद तक ठीक नहीं है। ऐसे में नेहरू परिवार के नाम जीत का सपना सजोना कारगर नहीं साबित होगा।

कांग्रेस की सबसे बड़ी आस अब भी राहुल गाँधी की भारत जोड़ों यात्रा पर लगी हुई है। तमाम विवादों के बाद भी राहुल की यात्रा के सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। परन्तु जब तक राज्यों का कुछ मुद्दों पर बचकाना बयान उनकी सोच को कठघरे में खड़ा कर देता है। राहुल के इर्द-गिर्द वामपंथी टीम उनको क्रान्तिकारी बनाने के

फिराक में लगी हुई है। इससे राहुल के कोंग्रेसी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। भारत जोड़ों यात्रा समाप्त होने के 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और तब तक ऐसे राजनीतिक हथकण्डे निष्प्रभावी हो जाते हैं। कांग्रेस की बागडोर मल्लिका अर्जुन खड़गे को अवश्य मिल गयी है लेकिन वह नेहरू परिवार की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस का पूरा संगठन राहुल की छवि गढ़ने में ही लगा हुआ है।

# क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक सक्रियता

## आम आदमी पार्टी (आप)

यद्यपि कि आप को तकनीकी रूप से राष्ट्रीय दल का तमगा मिल गया है लेकिन उनकी स्थिति दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित है। गुजरात और हिमाचल एवं गोवा के चुनाव में आप ने अपनी सक्रियता बढ़ा कर राष्ट्रीय पटल पर पहचान बनाने की कोशिश की है। आप नेता अरविन्द केजरीवाल का प्रयास है कि राजधानी का मुख्यमंत्री होने के नाते 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व विपक्षी दलों का जो भी गठबंधन हों उसमें उन्हें महत्व दिया जाये। लेकिन अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। आप ने जिस तरह से अभियान चलाया है उससे जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में 100 से ऊपर सीटों पर वह अपनी कवायत जारी रखेंगे।

## समाजवादी पार्टी (सपा)-

मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विश्ववास बढ़ा है। कांग्रेस एवं बसपा से गठबंधन के बाद सपा को कोई लाभ नहीं मिला। यही कारण है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश में अब एकेला चलो की राह पर चल रहे हैं। यूपी में भाजपा की टक्कर फिलहाल सपा से ही मिल रही है। सपा कार्यकर्ता अब भी स्थानीय से लेकर राज्य स्तर पर अब भी अन्य दलों से ज्यादा सक्रिय एवं संघर्षशील है। सपा कार्यकर्ताओं के जुझारूपन से अखिलेश लोकसभा चुनाव में 20 से अधिक सीटें जीतने की रणनीति बना रहे हैं।

राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन और चाचा शिवपाल के साथ आ जाने से भी अखिलेश की स्थिति में सुधार हुआ है। इसके बावजूद अखिलेश को MY(मुस्लिम-यादव) के गठजोड़ से बाहर निकल बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाना होगा। इसके लिए अन्य पिछड़ी जातियों तथा सवर्ण वर्ग का भी समर्थन हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के हटने से भी सपा को नुकसान हो सकता है।

## बहुजन समाज पार्टी (बसपा)-

बहुजन समाज पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाये हुए है। बसपा के पास अब भी दलित वर्ग का बड़ा तबका साथ में है लेकिन नेतृत्व के असमंजस के कारण कार्यकर्ता भी उदासीन है। बसपा नेता मायावती ऐन मौके पर पाला पदलने की धुरंधर खिलाड़ी है। ऐसे में किसी भी दल के लिए बसपा की उपेक्षा सही नहीं होगी।

## राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू)-

बिहार में राजद और जदयू गठबंधन में जातीय जनगणना शुरुवात कर नयी सियासी चाल चली है। बिहार की जाति राजनीति में भाजपा का हिन्दुत्व फार्मूला कभी प्रभावी नहीं रहा है। ऐसे में भाजपा के लिए बिहार में अपनी स्थिति को पूर्व की भांति बनाये रखने में कठिनाई हो सकती है। जातीय जनगणना की सियासत राजद और जदयू के लिए भी आसान नहीं होगी। बिहार में यादव कुर्मी के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां कुशवाहा, मांझी, केवट, की जाति पार्टियां काफी सक्रीय है। जातीय जनगणना के बाद अन्य दल भी सक्रिय होंगे ऐसे में अपने साथ मिलाय रखने में राजद और जदयू को इन जातियों के नेताओं को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी।

## अन्य दल-

तेलंगाना के टीआरएस नेता के° चंद्रशेखर राव ने भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए सबसे प्रयास किया और कई दलों के नेताओं से संपर्क किया परन्तु उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसी प्रयास में राव ने तेलांगना के राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली डेरा जमाया और भारतीय राष्ट्र समिति के नाम से नए दल का गठन किया। राव की यह रणनीति राष्ट्रीय राजनीति में कुछ कर गुजरने में सफल होगी ऐसा नहीं लगता है परन्तु उनके राज्य तेलंगाना में होने वाले चुनाव के लिए उन्हें अपनी सरकार बचाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है।

विपक्षी एकता की राजनीति में एनसीपी नेता शरद पवार, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसमें महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है तो बंगाल में ममता अपनी वर्चस्व बनायी हुई है।

इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक की सरकार है तो उड़ीसा बीजू जनता दल की सरकार है। फिलहाल यह दोनों एकलाचलों की रणनीति के तरह केंद्र सरकार से तालमेल बनाये हुए हैं। तमिलनाडु की AIADMK भाजपा के साथ गठबंधन में है। केरल में वामपंथी दलों का एकमात्र गढ़ बचा रह गया है। इस गढ़ को बचाने के लिए बामपंथी कहीं और किसी से भी गठबंधन को तैयार हैं। विपक्षी दलों की इसी खींचतान के चलते एकता का कोई माहौल नहीं दिख रहा है।

# अन्तिम दौर में पहुंची राहुल की भारत जोड़ो यात्रा

☐ अमन सिन्हा

**भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक जन आंदोलन है। जिसका उद्देश्य भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन एवं राहुल गाँधी द्वारा 7 सितंबर, 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। इसे मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, राजनीतिक केंद्रीकरण और विशेष रूप से "भय, कट्टरता" की राजनीति और "नफरत" के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था।**

## भारत जोड़ों यात्रा का सफर

इस यात्रा से पहले राहुल गांधी की छवि राजनीति में गंभीर राजनीतिक की नहीं थी। यहां तक कि कांग्रेस के भी कई नेताओं ने राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाए और कई पार्टी छोड़कर भी चले गए। लेकिन अब जबकि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी सबके सामने है। राहुल गांधी की छवि खुद ब खुद एक परिपक्व और मेहनती राजनेता के रूप में निखर कर सामने आयी है।

भले ही अखिलेश यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव जैसे विपक्षी दिग्गज यात्रा के साथ नहीं आए, लेकिन यात्रा का खुलकर विरोध या आलोचना करने का जोखिम उन्होंने भी मोल

नहीं लिया। वहीं कन्याकुमारी में डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन की मौजूदगी, महाराष्ट्र में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, दिल्ली में अभिनेता व राजनेता कमला हसन और उत्तर प्रदेश में नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूकअब्दुल्ला की यात्रा में मौजूदगी ने कांग्रेस को विपक्ष की धुरी बनाने की पटकथा लिख दी है। जबकि नीतीश कुमार शरद पवार और तेजस्वी यादव जैसे नेता यह साफ कर चुके हैं कि बिना कांग्रेस को घुरी बनाए विपक्षी एकता की बात निरर्थक है।

यह यात्रा की कामयाबी का ही असर है कि अखिलेश यादव और मायावती ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए शुभकामनाएं दीं हैं। यात्रा के उद्देश्य और मुद्दे ने ही अयोध्या के संतों और विहिप नेता व श्रीराम जन्मभूमि न्यास के सचिव चंपत राय को भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करने और शुभकामनाएं देने को बाध्य कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भले ही यात्रा को लेकर खामोशी अख्तियार कर रखी हो, लेकिन विरोध करने का जोखिम वह भी नहीं ले रहे हैं। जबकि यात्रा उनके प्रभाव क्षेत्र दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में है। हालांकि राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर बार-बार कहा है कि उनका उद्देश्य राजनीतिक और चुनावी नहीं है। कांग्रेस भी यही दोहरा रही है। लेकिन एक राजनीतिक दल का हर कदम राजनीतिक उद्देश्य से ही होता है। राहुल इस यात्रा के जरिए भारत जोड़ो का एक नया एजेंडा लेकर जनता के बीच गए हैं जो एक तरह से भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे का जवाब है। उनकी कोशिश संघ और भाजपा के हिंदू ध्रुवीकरण की बुनियाद पर बढ़ने वाले हिंदुत्ववादी एजेंडे के मुकाबले भारत की सामाजिक और धार्मिक एकता वाले समावेशी राजनीतिक एजेंडे को खड़ा करना है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश कह रहे हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद पार्टी में पश्चिम से पूरब पोरबंदर से परशुराम कुंड (अरुणाचल प्रदेश) तक की एक और भारत जोड़ो पदयात्रा करने पर विचार हो रहा है, अगर यह दूसरी यात्रा हुई तो 2023 में इसी यात्रा की अनुगूंज के बीच कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे और 2024 के लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस की दोनों यात्राओं का प्रतिफल भी सामने होगा।

## चंपत राय और पुजारी सत्येंद्र दास ने दी शुभकामनाएं

दिलचस्प है कि उत्तर प्रदेश में यात्रा की सफलता को लेकर तमाम किंतु परंतु थे, क्योंकि इस राज्य में कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महज दो सीटेंऔर दो फीसदी से कुछ ज्यादा वोट ही पा सकी थी। इसके बावजूद यहां न सिर्फयात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए बल्कि अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख कर्ताधर्ता और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय और राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी सत्येंद्र दास और अयोध्या के संत गोविंद गिरि ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं देकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा में राज्य के एक आंचलिक दल महान दल के नेता केशव देव मौर्य और उनके समर्थक भी शामिल हुए।

# टाइम लाइन

## तमिल नाडु

- **7 सितंबर 2022:** राहुल गांधी ने अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवि त्रिवल्लुवर को श्रद्धांजलि देने के बाद कन्याकुमारी में यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस यात्रा को "भारत का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम" कहती है, जहां लोगों की चिंताएं दिल्ली तक पहुंचेगी।
- **8 सितंबर 2022:** यात्रा का दूसरा दिन कन्याकुमारी के अगस्तीस्वरम में शुरू हुआ। राहुल गांधी ने BJP और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि "उन्हें लगता है कि झंडा उनकी निजी संपत्ति है"। यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, भूपेश बघेल और अन्य शामिल हुए।
- **9 सितंबर 2022:** यात्रा नागरकोइल में शुरू हुई, जिसमें राहुल गांधी स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज की मेजबानी कर रहे थे। उन्होंने उन किसानों से भी बातचीत की, जिन्होंने 2020-2021 के भारतीय किसानों के विरोध के दौरान विरोध किया था।
- **10 सितंबर 2022:** राहुल गांधी ने मार्तंडम में सफाई कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के एक स्थानीय समूह के साथ बातचीत की। वह दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं और उनके समर्थन में ट्वीट करते हैं। उसी दिन शाम को उन्होंने केरल में प्रवेश किया, केरल पीसीसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

## केरल

- **11 सितंबर 2022:** राहुल गांधी केरल में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनके स्वागत के लिए हजारों समर्थक और दर्शक इकट्ठा होते हैं। गांधी ने कहा कि यात्रा केरल में प्रचलित विचारों का विस्तार है।
- **12 सितंबर 2022:** भारत जोड़ो यात्रा में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अत्यधिक मतदान हुआ।
- **13 सितंबर 2022:** यात्रा तिरुवनंतपुरम के एक उपनगर कन्यापुरम से शुरू हुई, फिर से भारी मतदान हुआ।
- **14 सितंबर 2022:** यात्रा कोल्लम पहुंची, राहुल गांधी ने श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शिवगिरी मठ का दौरा किया।
- **15 सितंबर 2022:** राहुल गांधी और अन्य यात्रियों ने कोल्लम में दिन के लिए विश्राम किया।
- **16 सितंबर 2022:** यात्रा फिर से शुरू, राहुल गांधी ने कोल्लम में उद्यमियों और काजू श्रमिकों से मुलाकात की. कई काजू कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ अपनी शिकायतें साझा करते हैं, जिन्होंने आगामी संसदीय सत्र में इसे लाने का वादा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सत्ता में आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
- **17 सितंबर 2022:** यात्रा अलाप्पुझा जिला में प्रवेश करती है।
- **18 सितंबर 2022:** यात्रा का 11वां दिन हरिपाद से शुरू हुआ, राहुल गांधी का अंबालाप्पुझा में एक छोटी लड़की को उसकी सैंडल पहनने में मदद करने का एक वीडियो वायरल हो गया।
- **19 सितंबर 2022:** पुन्नपरा अरवुकड़, अलाप्पुझा से यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी ने केरल में स्थानीय मछुआरों के साथ ईंधन की बढ़ती लागत और कम सब्सिडी पर चर्चा की। गांधी दौड़ जीतते हुए केरल की प्रसिद्ध स्नेकबोट भी चलाते हैं। राहुल गांधी और यात्रा पर भाजपा नेताओं के अनुचित ट्वीट से कांग्रेस नाराज है।
- **20 सितंबर 2022:** भारत जोड़ो ने कोच्चि में प्रवेश किया। यात्रा में शामिल हुए सचिन पायलट।

- **21 सितंबर 2022:** कोच्चि के मदवाना गांव से यात्रा शुरू हुई।
- **22 सितंबर 2022:** यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज, अलुवा से यात्रा शुरू। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।
- **23 सितंबर 2022:** यात्रियों ने पेराम्ब्रा में विश्राम किया। भाजपा नेताओं ने झूठा आरोप लगाया कि यह पीएफआई के साथ एकजुटता में था, क्योंकि उसने उस दिन बंद का आह्वान किया था। कांग्रेस ने आराम की तारीख पहले ही तय कर ली थी।
- **24 सितंबर 2022:** त्रिशूर जिला में पेरम्बरा यात्रा फिर से शुरू हुई।
- **25 सितंबर 2022:** यात्रा त्रिशूर से शुरू हुई क्योंकि हॉलीवुड अभिनेता जॉनक्यूसैक ने राहुल गांधी के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया।
- **26 सितंबर 2022:** भारत जोड़ो यात्रा पलक्कड़ में प्रवेश करती है, पट्टांबी के रास्ते में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करती है।
- **27 सितंबर 2022:** यात्रा पुलमंटोल से शुरू होकर मलप्पुरम में प्रवेश करती है। भारत जोड़ी यात्रा को विनियमित करने की एक याचिका केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।
- **28 सितंबर 2022:** केरल में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन, क्योंकि यह तमिलनाडु से कर्नाटक की ओर बढ़ते हुए गुजरती है।
- **29 सितंबर 2022:** भारत जोड़ो अगले दिन कर्नाटक पहुंचने के कारण तमिलनाडु के गुडलुर में प्रवेश करती है।

## कर्नाटक

- **30 सितंबर 2022:** भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में गुंडुलपेटमें भारी भीड़ के साथ शुरू हुई जैसे कर्नाटक PCC नेताओं द्वारा राज्य में राहुल गांधी का स्वागत किया गया था।
- **1अक्टूबर2022:** भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में दूसरे दिन शुरू; PayCM का पोस्टर दिखाने पर पुलिस विभाग ने एक कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
- **2अक्टूबर2022:** बदनवालु से यात्रा शुरू, गांधी जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना जारी रखेगी। कांग्रेस ने कर्नाटक में COVID-19 संकट से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार पर भी निशाना साधा।
- **3अक्टूबर2022:** भारत जोड़ी यात्रा मैसूर में प्रवेश करती है, जहां राहुल गांधी एक भाषण देते हैं, बारिश का सामना करते हुए, "बारिश हो रही है, लेकिन BJP-RSS द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा को रोकने के खिलाफ यात्रा को कुछ भी नहीं रोक सकता है"।सोनिया गांधी मैसूर पहुंचती हैं, जहां उनका 6अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्रा में भाग लेने का कार्यक्रम है।
- **4अक्टूबर2022:** यात्रा मांड्या में दो दिन का ब्रेक लेती है।
- **5अक्टूबर2022:** यात्रा कल फिर से शुरू होगी।
- **6अक्टूबर2022:** सोनिया गांधी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, मांड्या से फिर से शुरू होने वाली यात्रा में शामिल हुईं। उन्होंने कई यात्रियों के साथ बातचीत की, जितनी महिलाएं उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ीं।
- **7अक्टूबर2022:** दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश का परिवार भारत जोड़ी यात्रा में शामिल हुआ क्योंकि यह सड़क पर 30 दिन पूरे करती है।कई शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों और शिक्षकों के साथ बातचीत के दौरान, राहुल गांधी ने कहा कि अकेले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय

भाषाओं की पहचान को खतरा पैदा करने का कोई इरादा नहीं था।

- **15अक्टूबर2022:** भारत जोड़ो यात्रा ने बेल्लारी जिले में पहुंचकर 1000किमी की यात्रा पूरी की।

## आंध्र प्रदेश

- **14अक्टूबर2022:** भारत जोड़ो यात्रा ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के डी. हिरेहल मंडल में प्रवेश किया।
- **18अक्टूबर2022:** भारत जोड़ो यात्रा कुरनूल जिले के हलहरवी में आंध्र प्रदेश में फिर से शुरू हुई।

## तेलंगाना

- **27अक्टूबर2022:** तीन दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नारायणपेट जिले के मकतल से फिर शुरु हो गई है।
- **29अक्टूबर2022:** तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के 52वें दिन और चौथे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ टॉलीवुड अभिनेत्री पूनम कौर महबूबनगर जिले के जडचेरला शहर की ओर चल रही थीं, जहां उन्होंने शाम को एक सभा को संबोधित किया।
- **31अक्टूबर2022:** शादनगर बस डिपो से थोंडा पल्ली, शम्शाबाद तक भारत जोड़ो यात्रा जारी रही। तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के को थुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान, राहुल गांधी ने कहा कि वह जाति आधारित जनगणना और सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आंकड़ों के प्रकाशन के पूर्ण समर्थन में हैं।
- **1नवंबर 2022:** दिवंगत दलित विद्वान रोहित वेमुला की मां हैदराबाद के रास्ते में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं। राहुल गांधी ने अपने पिता और तत्कालीन पार्टी प्रमुख राजीव गांधी द्वारा 19अक्टूबर1990 में उसी स्थान से सद्भावना यात्रा शुरू करने के 32 साल बाद, चारमीनार के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।यात्रा का रात्रि विश्राम सिकंदराबाद के बोवेनपल्ली में गांधी विचारधारा केंद्र में था।
- **2 नवंबर 2022:** अभिनेत्री-फिल्म निर्माता पूजा भट्ट यात्रा के 56वें दिन हैदराबाद में भारत जोड़ी यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुईं।

## महाराष्ट्र

- **7 नवंबर 2022:** 61वें दिन, भारत जोड़ी यात्रा 7 नवंबर, 2022 की शाम को महाराष्ट्र में प्रवेश कर गई।यात्रा तेलंगाना के जुक्कल निर्वाचन क्षेत्र के मदनूर मंडल के मेनुरु गांव से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले तक गई।
- **10 नवंबर 2022:** बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए।
- **16 नवंबर 2022:** कार्यकर्ता मेधा पाटकर वाशिम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं।
- **17 नवंबर 2022:** अभिनेत्री रियासेन महाराष्ट्र के अकोला में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं।राहुल गांधी ने दोहराया कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी।
- **18 नवंबर 2022:** महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी और अभिनेत्री मोना अम्बे गाँवकर बुलढाणा जिले के शेगाँव में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के साथ शामिल हुए।
- **19 नवंबर 2022:** इंदिरा गांधी की जयंती के दिन, अभिनेत्री रश्मि देसाई,आकांक्षा पुरी और नगमा बुलढाणा जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं।
- **20नवंबर2022:** अभिनेता अमोल पालेकर महाराष्ट्र में जलगाँव जामोद में अपने अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। निमखेड़ में एक लाइट शो का आयोजन किया गया जहां यात्रा ने राज्य में अपनी यात्रा समाप्त की।

## मध्य प्रदेश

- **23 नवंबर 2022:** भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के बोडर्ली गांव से प्रवेश कर गई।
- **24नवंबर2022:** प्रियंका गांधी और उनके पति

रॉबर्ट वाड्रा मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए।

## राजस्थान

- **4 दिसंबर 2022:** भारत जोड़ो यात्रा ने पहली बार कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में प्रवेश किया।
- **11 दिसंबर 2022:**अभिनेत्री दीगंगना सूर्यवंशी राजस्थान के बूँदी जिला में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं।
- **14 दिसंबर 2022:** आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए।
- **16 दिसंबर 2022:** गायिका सुनिधि चौहान ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर जयपुर के अल्बर्टहॉल म्यूजियम में एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी।
- **19 दिसंबर 2022:** राजस्थान के अलवर में एक रैली को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने अंग्रेजी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि राजस्थान में लगभग 1,700 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं।उन्होंने कहा कि भाजपा नेता नहीं चाहते कि स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जाए। लेकिन उनके सभी नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाते हैं.

## हरियाणा

- **21 दिसंबर 2022:** भारत जोड़ो यात्रा नूँह जिला के मुंडकाबॉर्डर से हरियाणा में दाखिल हुई। झंडा सौंपने के समारोह के बाद हरियाणा के नूंह में पाटन उदयपुरी से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू हुई।
- **23दिसंबर2022:** DMKसांसद एम°के° कनिमोझी हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं।

## दिल्ली

- **24 दिसंबर 2022 :** एनएचपीसी मेट्रो स्टेशन से यात्रा फिर से शुरू करने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली में प्रवेश किया। लाल किला में अपने भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने 2,800 किलोमीटर पैदल चलने के दौरान लोगों के बीच कोई नफरत या हिंसा नहीं देखी।भारत जोड़ो यात्रा ने कन्याकुमारी में गांधी मंडपम से दिल्ली में लाल किले तक 3,122किमी की दूरी तय की।

## उत्तर प्रदेश

- **3 जनवरी 2023:** भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद जिले में लोनी सीमा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।रॉ के पूर्व प्रमुख ए.एस. दुलत और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूकअब्दुल्ला भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए।
- **5 जनवरी 2023:** बॉलीवुड अभिनेत्री रितु शिवपुरी शामली, उत्तर प्रदेश में 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुईं।

## पंजाब

- **10 जनवरी 2023:** भारत जोड़ो यात्रा ने शंभू सीमा के माध्यम से पंजाब में प्रवेश किया। राज्य में यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया।

**कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और 31 जनवरी 2023 से पहले श्रीनगर में खत्म होगी।कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' और 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की लगभग 4,260 किलोमीटर की भारत यात्रा की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा के अंत में एक "नई, युवा और आक्रामक कांग्रेस" उभरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा पार्टी के लिए बूस्टरडोज की तरह काम करेगी। "यह कांग्रेस के लिए पुनरुद्धार योजना का एक हिस्सा है"।**

# जोशीमठ का दर्द

□ जितेन्द्र सिंह चैहान

उत्तराखंड के गढ़वाल के पैनखंडा परगना में समुद्र की सतह से 6107फीट की ऊँचाई पर, धौली और विष्णुगंगा के संगम से आधा किलोमीटर दूर जोशीमठ की उत्पत्ति की कहानी आदि शंकराचार्य से जुड़ी है। आठवीं-नवीं शताब्दियों में की गई जिनकी हिमालयी यात्राओं ने उत्तराखंड के धार्मिक भूगोल को व्यापक रूप से बदल दिया था।

दक्षिण भारत के केरल राज्य के त्रावणकोर के एक छोटे से गाँव में जन्मे आदि शंकराचार्य ने वेदान्त दर्शन के प्रसार-प्रचार के उद्देश्य से बहुत छोटी आयु में अपनी मलयालम जड़ों से निकल कर सुदूर हिमालय की सुदीर्घ यात्राएँ कीं और असंख्य लोगों को अपना अनुयायी बनाया। इन अनुयायियों के लिए उन्होंने चार दिशाओं में चार मठों का निर्माण किया- पूर्व में उड़ीसा के पुरी में वर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिका का शारदा मठ, दक्षिण में मैसूर का श्रृंगेरी मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ में नारायण के ध्वस्त मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा कराने के उपरान्त वे केदारनाथ गए, जहाँ 32 साल की छोटी सी उम्र में उनका देहांत हो गया।

## आदि शंकराचार्य को मिला दिव्य ज्ञान

जोशीमठ की ऐतिहासिक महत्ता इस जन-विश्वास में निहित है कि आधुनिक हिन्दू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य ने यहाँ शहतूत के एक पेड़ के नीचे समाधिस्थ रह कर दिव्य ज्ञान हासिल किया

था। इसी कारण इसे ज्योतिर्धाम कहा गया। यह विशाल पेड़ आज भी फलता-फूलता देखा जा सकता है और इसे कल्पवृक्ष का नाम दे दिया गया है।

फ़िलहाल इस वृक्ष से लगा मंदिर भी टूट चुका है और वह गुफा भी ध्वस्त हो चुकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ शंकरा चार्य ने साधना की थी। जोशीमठ के बारे में अनेक धार्मिक मान्यताएँ प्रचलन में हैं। यहाँ भगवान नृसिंह का मंदिर है, जहाँ भक्त बालक प्रह्लाद ने तपस्या की थी। अनेक देवी-देवताओं के मंदिरों के अलावा यहाँ कई देवताओं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, भृंगी, ऋषि, सूर्य और प्रह्लाद के नाम पर अनेक कुंड भी हैं। ये तथ्य इस छोटे से पहाड़ी नगर को देश के धार्मिक मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाते हैं।

## क्यों दरक रहा है जोशी मठ

बद्रीरनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन का रास्ता यहीं से होकर जाता है।आम दिनों में अगर आप यहां हो तो खूबसूरती के साथ रोमांच का एहसास होगा, फिलवक्त डर का माहौल है। जमीन दरक रही है, पूरे शहर पर ढह जाने, तबाह होजाने का खतरा मंडरा रहा है। मीडिया में आप जोशीमठ के बारेमें लगातार सुन रहे होंगे। वहां हो रहे प्रदर्शनों की तस्वीर भी देखी होगी।

पिछले कुछ दिनों से जोशी मठ के घरों में लगातार दरार की खबरें आ रही थीं, बीतेसाल नवंबर में ये सिलसिला शुरू हुआ। अब नेशनल लेवल पर चर्चा तब होने लगी, जब मुख्य सड़क में बड़ी दरार आ गई। घरों के ढह जाने का खतरा बढ़ा तो स्थानीय लोग सड़क पर मशाल जुलूस के जरिए विरोध प्रदर्शन करने लग गए।

जोशी मठ के मारवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी 2023 की दोपहर बाद जमीन फाड़कर अचानक से पानी निकलने लगा। वहां जेपी कंपनी के 35 भवनों को आनन-फानन में खाली कराया गया क्योंकि वहां पानी का जलस्तर दोगुना हो गया है। कई लोगों ने अपना घर छोड़ रिश्तेदारों के यहां पनाह ली, तो प्रशासन ने भी ऐतिहात के तौर पर 93 मकानों को लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इलाके में 561 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें रविग्राम में 153, गांधीनगर में 127, मनोहर बाग में 71, सिंहधार में 52, परसारी में 50, अपर बाजार में 29, सुनील में 27, मारवाड़ी में 28 और लोअर बाजार में 24 मकान खतरे की नोंक पर टिके हैं।

जोशीमठ में भू-धंसाव को लेकर बृहस्पतिवार को क्षेत्र में बाजार पूरी तरह से बंद रहा। प्रभावित लोगों ने दिनभर बदरीनाथ हाईवे पर चक्का जाम रखा। लोगों की चिंताएं और गुस्सा जायज है क्योंकि यहां किसी भूकंप की वजह से दरार नहीं आई। ना ही कोई हिमस्खलन हुआ है बल्कि ये एक तरह का मैन-मेड-डिजास्टर है। सरकार और कंपनियों की गलती का नतीजा। क्या है वोगलितयां जिसमें लालच छिपा है? इस पर आएं,

उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लालच किसी चीज को लील रहा है सिर्फ इंसानी जमीन नहीं इतिहास खतरे में है।

## क्या है इतिहास?

जोशीमठ में विष्णुभगवान को समर्पित एक लोकप्रिय मंदिर है। इसके अतिरिक्त नरसिंह, वासुदेव, नवदुर्गा आदि के मंदिर भी यहां पर हैं। जोशीमठ का रिश्ता इतिहास की एक औरबड़ी घटना से है। जोशीमठ से कुछ 15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है. रैणी नाम का। मार्च 1974 की में इसी गांव की रहने वाली गौरा देवी गांव की औरतों को लेकर जंगल पहुंची और उनसे चिपट गई. पेड़ काटने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा, "अगर पेड़ काटने हैं तो पहले हम पर गोली चलाओ". यहां से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की। जिसके चलते सरकार को झुकना पड़ा और इस इलाके में पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई। वर्तमान आपदा से इस आंदोलन का एक रिश्ता ये भी है कि कुछ वक्त पहले आपदा के कारण गौरा देवी की मूर्ति रैणी से जोशीमठ तहसील में ट्रांसफर करनी पड़ी थी तो ये सिर्फ किसी शहर के दरकने की घटना नहीं है, बल्कि हमारे पुरखों का समृद्ध इतिहास उन दरारों में फंसा हुआ है।

फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने की वजह से चमोली में मौजूद NTPC के प्लांट में तबाही हुई थी. दर्जनों लोगों की जान गई। स्थानीय लोग कहते हैं उसी एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार हैं। जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग निकाली जा रही है। जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किए गए थे, जिसकी वजह से हालत खराब हो रही है। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाई पास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है।

ऐसा नहीं है कि ये आपदा कोई अचानक से आ गई है। 1976 यानी आज से 48 साल पहले, जोशीमठ पर बढ़ते इस खतरे पर मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में आगाह कर दिया गया था। 1976 में जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तब तत्कालीन गढ़वाल के कमिश्नर एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। जिसमें शहर के धंसने का जिक्र है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से हुए भवन निर्माण से सत्तर के दशक में भी लोगों ने भूस्खलन और सड़क में दरार की शिकायत की थी। जिसके बाद कमेटी बनी, रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में मौजूद है और ये शहर पहाड़ से टूटे टुकड़ों और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है। जिसकी वजह से नींव कमजोर है। समिति ने भूस्खलन और भू-धसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर वहां पौधे लगाने की सलाह दी थी, बड़े निर्माण ना करने की चेतावनी भी।

साल 2001 में उत्तराखंड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर के निदेशक MPS बिस्ट और पीयूष रौतेला ने भी एक ऐसा

ही रिसर्च सबमिट की थी, जिसमें जोशीमठ के सेंट्रल हिमालयन और भूकंप जोन होने की बात लिखी गई थी। तमाम संकेतों और सुझावों को दरकिनार किया गया। किसी सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया। नतीजा सामने है। इसके अलावा अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों ही नदियां जोशीमठ शहर के नीचे की मिट्टी का कटान कर रही हैं, जानकार मानते हैं कि भूस्खलन के मामले में ये क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है. हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से ज्यादा समस्या हो रही है। यहां पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या और अनियोजित विकास भी समस्या की वजह है। जोशीमठ में भारी भवन निर्माण की शुरुआत साल 1962 के बाद से हुई।1962 में चीन केसाथ युद्ध के बाद इलाके में तेजी के साथ सड़क मार्ग का विकास हुआ. सेना के कैंप बनने के अलावा हेलिपैड बने। शहर के बढ़ते महत्व को देखते हुए यहां बसावट बढ़ती चली गई। कई होटल खुले। लोगों ने कारोबार शुरू किया।औली और बद्रीनाथ समेत हेमकुंड साहिब तीर्थ ने उनके कारोबार को बढ़ाने के साथ-साथ इसे देशभर के लोगों का पसंदीदा शहर बना दिया। यहां कई ऐसे होटल हैं, जो 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए। अब सबकुछ खतरे में है।

टाइम्स इंटरनेट की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने जोशीमठ में तेजी से हो रहे भू-धंसाव का अध्ययन किया है.उन्होंने आर्काइव सैटलाइट तस्वीरों की मदद से यह निष्कर्ष निकाला है कि जोशीमठ का रविग्राम हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है। इसका मतलब यह भी है कि ये कोई भूस्खलन का असर नहीं है, बल्कि ये हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है।जो बहुत ही ज्यादा यानी अलार्मिंगसिग्नल है औरजो सबसे दुखद बात है वो ये कि भू वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अब इन दरारों को भर पाना लगभग असंभव है। एक पूरा शहर तबाह हो जाने की दिशा में बढ़ चुकाहै। भू वैज्ञानिक डॉ एसपी सती बहुत गंभीर बात बता रहे हैं।

स्थिति भयावह हो चली है। मकान-दुकान को छोड़ दीजिए, अब हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। देर हो चुकी है, मगर अब प्रशासन हरकत में है। बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रोपावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलांग बाइपास रोड के काम को भी रोक दिया गया है। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे 'ऑलीरोपवे' के परिचालन को भी रोक दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ में स्थिति पर करीब से नजररखी जा रही है, भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले ‘जोन-5’ में आने वाले इस शहरका सर्वे करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भी गठित किया गया है. मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं।

दुर्भाग्य ये है कि सरकारें तब जागती हैं, जब जिंदगियां खतरे में आ चुकी होती हैं। एक समृद्ध विरासत, अध्यात्म, धर्म और पर्यटन का शहर, जहां जमीन के नीचे की धूल धीरे-धीरे गुबार का शक्ल ले रही है। वक्त रहते अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किस्से कहानियों में ही जोशीमठ रह जाएगा। यहां के पहाड़ अब और बोझ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं और ना ही किसी सुरंग की सुराख सहने की।

# नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या 2014 से 1.7 गुना बढ़ी

**❑ सुजीत श्रीवास्तव**

भारत रोजाना 600 से अधिक लोग भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं। भारत के आजादी के 75वें अमृत वर्ष काल में रोजाना उच्च आय श्रेणी वाले भारतीय नागरिक नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, यह अपने आप में गंभीर सवाल है।

विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 के पहले 10 महीनों में 1,83,741 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, यानी हर दिन 604 लोग देश छोड़कर जा रहे हैं।

वर्ष 2014 में रोजना औसतन 354 लोग भारत की नागरिकता छोड़ते थे वो संख्या अब 604 हो गई है।

यह जानकर लोगों को हैरानी होगी कि जो लोग देश छोड़कर जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग उच्च आय श्रेणी वाले हैं। 2022 में जो लोग देश छोड़कर गए उनमें अधिकतर लोगों की आय आठ करोड़ रुपये से ज्यादा थी।

लोगों के भारत की नागरिकता त्यागने के कई कारण हैं। मसलन, लगातार बढ़ती बेरोजगारी है, जीडीपी विकास दर लगातार कम है, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में हैं, वैश्विक भूख सूचकांक में 121 देशों में हम 107वें स्थान पर हैं, वैश्विक स्त्री-पुरुष अंतर अनुपात में

# हर साल नागरिकता छोड़ रहे भारतीय

## 2019 से 2021 के दौरान 3,92,643 लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता

| 2020 में | 2019 में | 2021 में |
|---|---|---|
| 85,256 | 1,44,017 | 1,63,370 |

भारत की स्थिति बहुत खराब है और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता की सूची में दुनिया में भारत का स्थान 150वां है।'

भारतीयों ने अब घरेलू के बजाय विदेशों में निवेश करना शुरू कर दिया है। भारत की वैश्विक रैंकिंग लगातार उच्च बेरोजगारी अनुपात के साथ विभिन्न मानकों पर गिर रही है।

सीएमआईई के आंकड़ों के हवाला से 2022 में 12 में से 9 महीनों में बेरोजगारी का स्तर 7 प्रतिशत से अधिक था और दिसंबर 2022 में यह आंकड़ा 8.3 प्रतिशत था और शहरी बेरोजगारी के मामले में यह 10.9 प्रतिशत था।

नोटबंदी के दोहरे झटकों और जीएसटी के त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन के कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि वित्त वर्ष 2017 में 8.3 प्रतिशत से गिरकर वित्तीय वर्ष 2020 में 3.7 प्रतिशत हो गई और अर्थव्यवस्था अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है।

# M/s. Chauhan Pen Center

**Deals in: All kind of Stationery & Govt. General order Supplier**

JITENDER KUMAR SINGH : 9335244977

53- Gwynne Road, Aminabad, Lucknow 226018

# Vaishno Marble & Traders

Deals in: All types of Marble, Granite Kota, Tiles etc.

**Mobile: 9415034158, 9369106489**